

राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष : 25 अंक : 1

फरवरी 2002



अरिवल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

हार्दिक शुभकामनाओं सहित



सिद्धोमल प्रतिष्ठान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय

छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

॥ प्रकाशक ॥

संपादक
आशुतोष

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

कि

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

क्रीड़ा-क्रीड़ा काल

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्



अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्

भारत का अग्रमान्य छात्र संगठन जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता को वैश्विक समुदाय में गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त कर एक शक्तिमान, समृद्धशाली एवम् स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में पुनर्निर्माण करने के भव्य लक्ष्य से प्रतिबद्ध है।

छात्र शक्ति-राष्ट्र शक्ति

॥ वन्दे मातरम् ॥

राष्ट्रीय छात्रशक्ति
का प्रकाशन
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्
द्वारा
अभावपि कार्यालय
16/3676, रैगरपुरा, करोलबाग,
नई दिल्ली-110005
से किया गया।

संपादक
आशुतोष

मुद्रक
श्रीराम एण्टरप्राइजेज
एम-71, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32

राष्ट्रीय छात्रशक्ति
को
और अधिक श्रेष्ठ
एवं छात्रोपयोगी
बनाने हेतु
आपके
सुझाव एवं सहयोग
अपेक्षित हैं।
आपके विचार
'संपादक के नाम पत्र'
स्तंभ के अंतर्गत
प्रकाशित किये जायेंगे।

भवदीय
संपादक



सम्पादकीय

वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ 1835 में जब शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा की ब्रिटिश नीति निर्धारित की। 112 वर्षों तक यह व्यवस्था बिना किसी विशेष गतिरोध के चलती रही।

स्वाधीनता आन्दोलन से जुड़े कुछ शिक्षाशास्त्रियों ने इस प्रणाली के विकल्प की खोज में अनेक प्रयोग किये। स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रारंभ तथा बाद में आर्य समाज के प्रयत्नों से विशेषकर उत्तर भारत में फैली एंग्लो-वैदिक कॉलेजों की शृंखला, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर का शांति निकेतन, महात्मा गांधी द्वारा बुनियादी तालीम का प्रसार, मालवीय जी द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना आदि इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। श्री अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द, डॉ. राधाकृष्णन, डॉ. जाकिर हुसैन आदि ने भी शिक्षा के विषय में गंभीर चिन्तन किया तथा समय-समय पर अपने विचार व्यक्त किये।

तत्कालीन भारतीय शिक्षाशास्त्रियों के विचार कितने भी उपयोगी क्यों न रहे हों, अंततः वे गुलामों के प्रतिनिधि थे और शिक्षा की ब्रिटिश नीति में उनके विचारों का कोई मूल्य नहीं था। चूँकि शिक्षा का उद्देश्य भारतीय संदर्भों से नहीं जुड़ा था इसलिये भारतीय प्रतिनिधियों से चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी।

स्वतंत्र भारत में शिक्षा के निर्धारण का काम जिन लोगों को सौंपा गया, दुर्भाग्य से उनकी निष्ठा के केन्द्र भी विदेश में थे। भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन तथा भारतीय वाङ्मय को वे हिकारत भरी नजरों से देखते थे। उनका दम भी अंग्रेजों से किसी मायने में कम न था। वे एक निश्चित विचारधारा-वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते थे और उनका यह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उनका एकाधिकार है। पांच दशकों तक यह एकाधिकार चला भी।

इस काल खंड में भी शिक्षा क्षेत्र में अनेक प्रयोग हुए। विद्याभारती जैसी संस्था अस्तित्व में आई जिसने पूरे देश में अपना प्रसार किया और 14,000 से अधिक पूर्व प्राथमिक से लेकर महाविद्यालयों की स्थापना व सफल संचालन द्वारा अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। शिक्षा क्षेत्र की नियामक संस्थाओं पर काबिज वामपंथी विद्वानों की इस संदर्भ में स्पष्ट नीति थी-जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है उसे शिक्षा क्षेत्र में अस्पृश्य बनकर रहना होगा। उनके एक प्रमुख विचारक ने अपने इन 'प्रतिद्वंदी' शिक्षा शास्त्रियों को अनेक बार 'जड़, जाहिल और ठूठ' के विशेषणों से नवाजा है। जिन्हें वे शिक्षाविद् के रूप में मान्यता ही नहीं देते उनके साथ शिक्षा पर चर्चा का सवाल ही नहीं पैदा होता।

लोकतंत्र की बलिहारी, सत्ता में एक परिवार तथा एक दल के प्रभुत्व का मिथक टूटा। साथ ही क्षीण हुआ वामपंथी बौद्धिकता का प्रभामंडल भी। जिन बुद्धिजीवियों ने पांच दशक तक सत्ता का अप्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष सुख लिया और बदले में शिक्षा को सत्ता के पल्लू से बांधे रखा, राजनीति ने जब करवट बदली तो परिवर्तन की लहरों ने उन्हें मुख्यधारा से निकालकर किनारे पर ला पटक।

संस्थान भी वही है, नीतियां भी वही हैं। बस 'वे' नहीं हैं। और जहाँ 'वे' नहीं है वहाँ जो भी हो रहा है वह सब गलत है, प्रतिगामी है, सांप्रदायिक है, फासीवादी है, भगवाकरण है। अस्पृश्यता का भाव वे आज भी नहीं भुला सके हैं। एक साथ बैठकर चर्चा के लिये 'वे' आज भी तैयार नहीं। हाँ, विवाद जरूर पैदा कर रहे हैं। शिक्षा में होने वाले परिवर्तन पर 'वे' अपने विचार उपयुक्त मंचों पर कम, धरने, प्रदर्शन और जुलूसों में अधिक व्यक्त कर रहे हैं। बीरबल्लु हट्ट का आलम यह है कि आज वे उन्हीं नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें तय करने में 'वे' खुद शामिल थे।

शिक्षा के 'भारतीयकरण' की जो पहल हुई है उसे और अधिक बेहतर बनाने में आलोचकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। विडंबना यह है कि आलोचक चर्चा में भागीदारी के बजाय निरर्थक विवादों को जन्म दे रहे हैं तथा अकादमिक बहस को राजनैतिक दांव-पेंच में उलझा रहे हैं।

'राष्ट्रीय छात्र शक्ति' ने शिक्षा के भारतीयकरण की चर्चा को अपने इस अंक के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इस विषय में पाठकों के विचार एवं प्रतिक्रियाओं का स्वागत है।

With Best Compliments



THE DELHI MAHARASHTRIYA SAMAJ BUILDING TRUST (REGD.)

Brihan Maharashtra Bhawan

Opp. Paharganj Police Station

New Delhi - 110 055

Ph. : 7779008, 7770520, Gram : Brumlodge

गीत

शील का संकल्प लेकर, ज्ञान के अभियान में,
बढ़ रहा है छात्र सारा, हर नगर हर ग्राम में॥
बढ़ रहे हैं चरण अगणित, गूँजते हैं नित्य स्वर,
मातृभू की अर्चना में, दीप जलते हैं प्रखर,
ज्ञान हो सबके लिये और, सृजन हो विज्ञान से।

हर नगर - हर ग्राम से॥1॥

भेद-भावों को मिटाकर, साधना है चल रही,
भोग के भीषण तिमिर में, त्याग ज्योति जल रही
मृत्युभी भयभीत हमसे, डर नहीं तूफान से

हर नगर-हर ग्राम से॥2॥

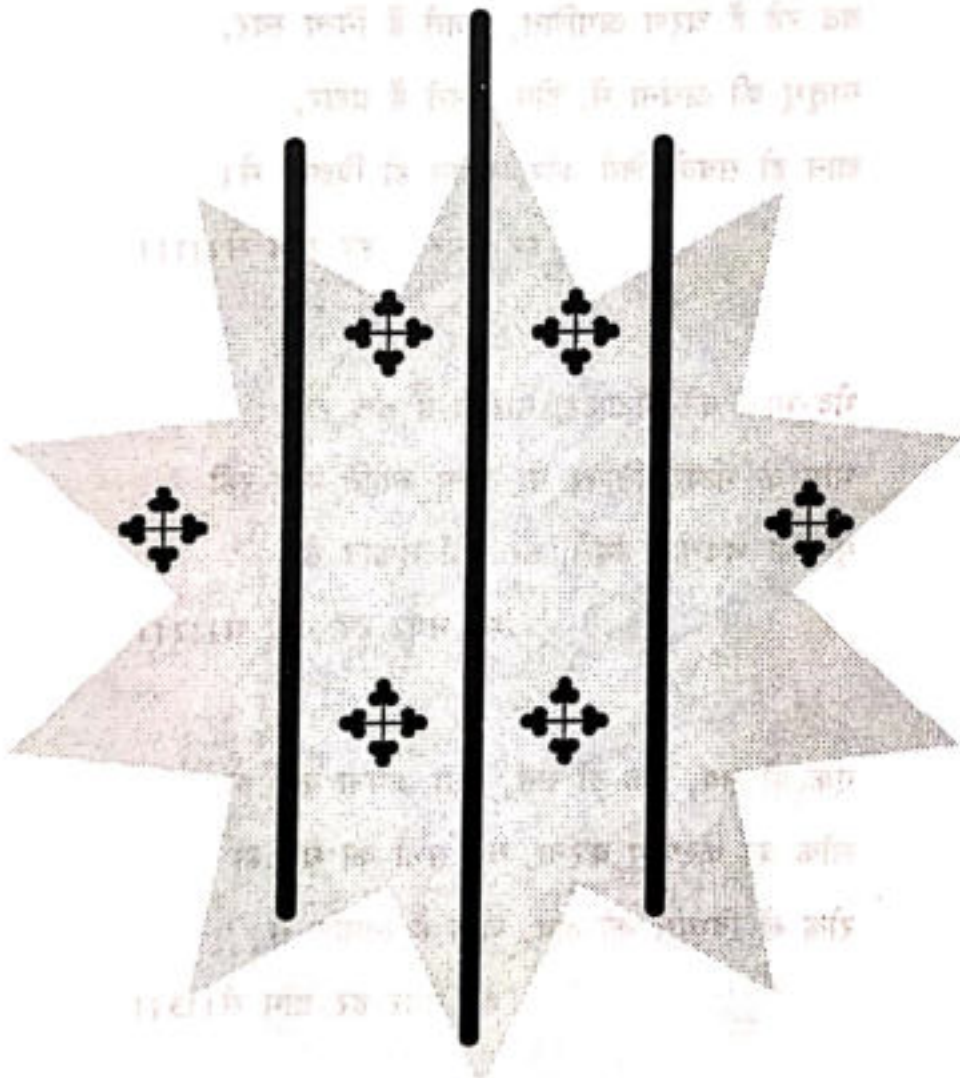
एक हों सब, नेक हों सब, ऐसा अपना कर्म हो,
लोक का कल्याण करना, यह सभी का धर्म हो
रोक लें विध्वंस को अब, जीत है निर्माण में

हर नगर-हर ग्राम से॥3॥

ध्येय के पथ पर बढ़ें हम, रुक न पायें ये कदम
एकता का मंत्र गूँजे, गीत ऐसे गायें हम
विश्वविजयी भारती की, आरती निज प्राण से

हर नगर-हर ग्राम से॥4॥

With Best Compliments



CENTRE OF EXCELLENCE

16, New Rohtak Road
New Delhi

अभाविप का 47वाँ राष्ट्रीय अधिवेशन सम्पन्न

राष्ट्रीय आंकाक्षाओं को साकार करती है छात्र शक्ति

गुवाहाटी। शिक्षा वही है जो हमारे स्वाभिमान को जगाती है, पुरुषार्थ को जगाती है। भारत की श्रद्धा को नष्ट करने वाली, हमारी जड़ों को खोदने वाली, हमारी अस्मिता, श्रद्धा, शक्ति और मानदण्डों का अनादर करने वाली शिक्षा इस देश की छात्र शक्ति को नहीं दी जानी चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के 47वें राष्ट्रीय अधिवेशन के सार्वजनिक समारोह में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी ने उक्त उद्गार प्रकट किये।

छात्रशक्ति का आह्वान करते हुए श्री जोशी ने कहा कि आप जीवन के जिस क्षेत्र में जायें, अपने यौवनपूर्ण तेज के साथ जायें। हर संकट के समाधान के लिये नचिकेता की भाँति विश्वास आप में हो। हम सभी स्वाभिमानी राष्ट्र के पुरुषार्थी नागरिक हैं। धिर पुरातन संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं।

उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारी माँ है। भारत की आत्मा है। भारत ने दुनियाँ को दर्शन दिया है। सारे ब्रह्मांड से हम जुड़े हुए हैं। आज हमें अपने अंदर स्व और विवेक को जागृत करना है। स्व की पहचान ही हमारी अस्मिता है। देश के युवाओं के पास प्रखर बुद्धि है, प्रतिभा है। लेकिन अपनी

शक्ति का अनुभव तभी कर सकते हैं जब हमें अपनी अस्मिता की पहचान हो।

श्री जोशी ने कहा कि हम पहले उत्पन्न हुए इसलिये विश्व में अग्रज होने के कारण सारे ब्रह्मांड के नागरिकों को सुसंस्कृत करने का काम हमारा है। हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे तथा शक्तिशाली, पराक्रमी एवं वैभवशाली भारत का निर्माण करेंगे।

प्रसिद्ध असमिया फिल्म निर्माता जहानू बरूआ ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र देश का निर्माता है। फिल्मों में हम कल्पना को साकार करते हैं और छात्रशक्ति राष्ट्रीय आकांक्षाओं को साकार करती है।

समारोह से पूर्व देश भर से आये प्रतिनिधियों की भव्य शोभायात्रा डिगली पुखरी से प्रारंभ होकर चांदमारी ग्राउंड पहुंची। पारंपरिक वेश-भूषा में प्रतिनिधि भारत माता की जय एवं कश्मीर हो या गोहाटी अपना देश अपनी माटी जैसे नारों का उद्घोष करते चल रहे थे। मार्ग में अनेक स्थानों पर नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया।

भाषण सत्र में "देश की वर्तमान स्थिति" पर अपने

नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद्

पदाधिकारी सूची

अध्यक्ष	- डॉ. कैलाश शर्मा, जयपुर	- श्री सुनील बंसल, जयपुर
		- सुरेश भट्ट, आगरा
उपाध्यक्ष	- श्री एल.आई. सिंह, मणिपुर	- सुश्री सुनीता लाठ, भुवनेश्वर
	- श्री पी. सुबैया, चेन्नई	
	- श्री राम नरेश सिंह, कटिहार	संगठनमंत्री - श्री द्वात्रेय होसबाले, मुंबई
	- श्री दत्ता नाईक, गोआ	
	- सुश्री शोभा पैठणकर, इन्दौर	सह संगठन मंत्री - श्री बी. सुरेन्द्र, चेन्नई
		- श्री सुनील अम्बेकर, नागपुर
महामंत्री	- श्री रमेश पप्पा, दिल्ली	
		कोषाध्यक्ष - श्री विजय वैद्य, मुम्बई
मंत्री	- श्री अतुल कोठारी, दिल्ली	
	- श्री के. रघुनंदन, बेंगलूर	कार्यालय मंत्री - श्री शरद चव्हाण, मुम्बई

विचार व्यक्त करते हुए परिषद् के पूर्व अध्यक्ष श्री दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि दुनियां ने आतंकवाद के खिलाफ आज लड़ाई शुरू की है किन्तु भारत इस लड़ाई को पिछले दो दशकों से लड़ रहा है। 55,000 से अधिक लोग इस छायायुद्ध में मारे गये हैं। जम्मू-कश्मीर में जहाँ सौ से भी अधिक आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में घर्ष के समर्थन से अलगाववादी गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चल रही हैं। आई.एस.आई. की मदद पर चलने वाले भाड़े के सैनिक हमारी अस्मिता पर चोट कर रहे हैं।

श्री गोस्वामी ने कहा कि उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार तथा नौकरशाह, नेता और अपराधियों के बीच गठजोड़ देश की अस्मिता के लिये चुनौती बनकर उभरा है। सामाजिक तनाव, अस्पृश्यता निरक्षरता, अंधविश्वास, कन्या शिशु वध जैसी कुरीतियाँ आज भी विद्यमान हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से परिषद् से सड़क तक तथा अपने घर में भी सामाजिक उत्पीड़न पर प्रतिक्रिया एवं सामाजिक समरसता के प्रयास में जुटने तथा गौरवशाली संस्कृति, प्राचीन सभ्यता व स्वर्णिम इतिहास रूपी धरोहर को बनाये रखने का आह्वान किया।

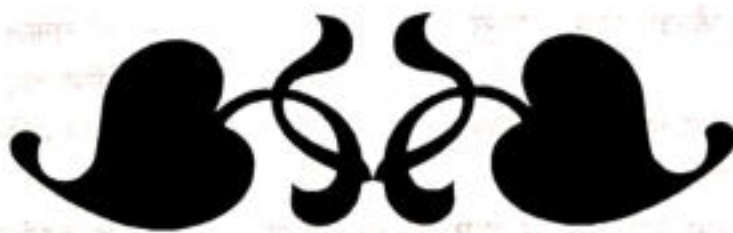
“शिक्षा” विषय पर निवर्तमान महामंत्री श्री अतुल कोठारी का भाषण हुआ। परिषद् के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री

सुनील अम्बेकर ने अपने भाषण में संगठन की विशिष्ट कार्य पद्धति पर प्रकाश डाला। अधिवेशन में “उच्च शिक्षा की शुल्क संरचना”, “शिक्षा का भगवाकरण-मिथ्या प्रलाप”, “वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य” एवं “घुसपैठ : एक राष्ट्रीय समस्या” विषयों पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किये गये।

स्व. प्रा. यशवंतराव केलकर की स्मृति में स्थापित युवा पुरस्कार “लोकसंगीत के लोकप्रियकरण एवं संवर्धन” के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिये समस्तीपुर, बिहार की सुश्री लक्ष्मी कुमारी को दिया गया। इसके अंतर्गत रुपये 10,000/- की राशि एवं मानपत्र प्रदान किये गये।

संगठन के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कैलाश शर्मा तथा नवनिर्वाचित महामंत्री श्री रमेश पण्णा ने अपना पदभार ग्रहण किया। अगले वर्ष के लिये नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद् की घोषणा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। निवर्तमान महामंत्री श्री अतुल कोठारी ने गत वर्ष में पूरे देश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किये गये कार्यक्रमों, आंदोलनों एवं छात्रसंघ चुनावों में अभावित की भूमिका की जानकारी देने वाला महामंत्री प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अधिवेशन में देश के सभी प्रदेशों के 335 जिलों के 405 स्थानों से कुल 1064 कार्यकर्ता सम्मिलित हुए जिनमें 117 छात्राएँ एवं 72 शिक्षक प्रतिनिधि थे।

With Best Compliments



M/s Chandu Construction

101, Sunder Apartments

Sardar Balwant Singh Basi Marg, Margam Circle

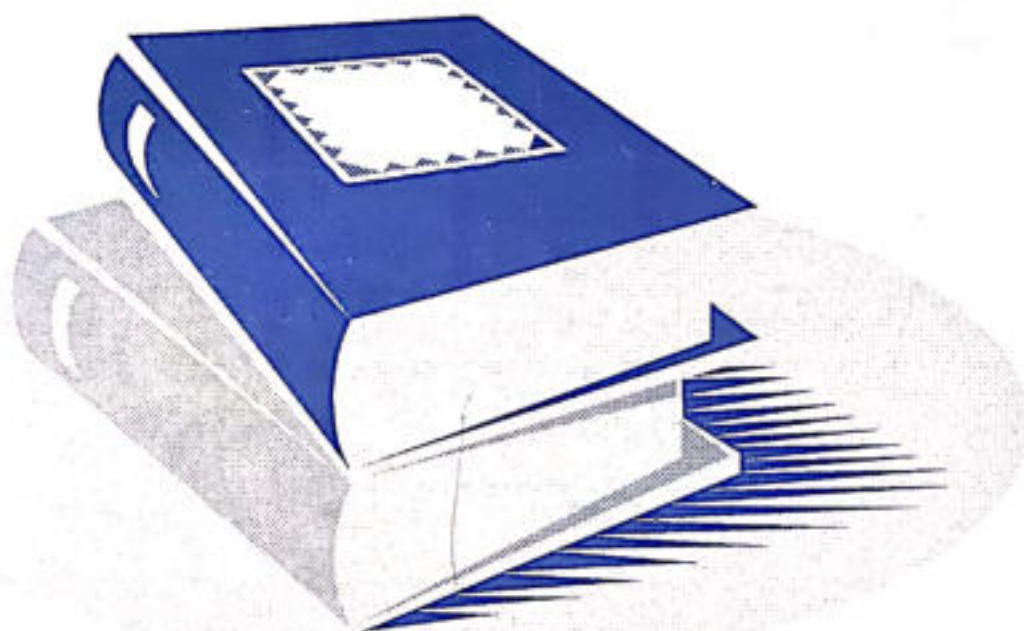
Mumbai - 400 010



राष्ट्रीय अधिवेशन, गोहाटी में सुश्री लक्ष्मी कुमार को केलकर युवा पुरस्कार प्रदान करते हुए माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी



With Best Compliments



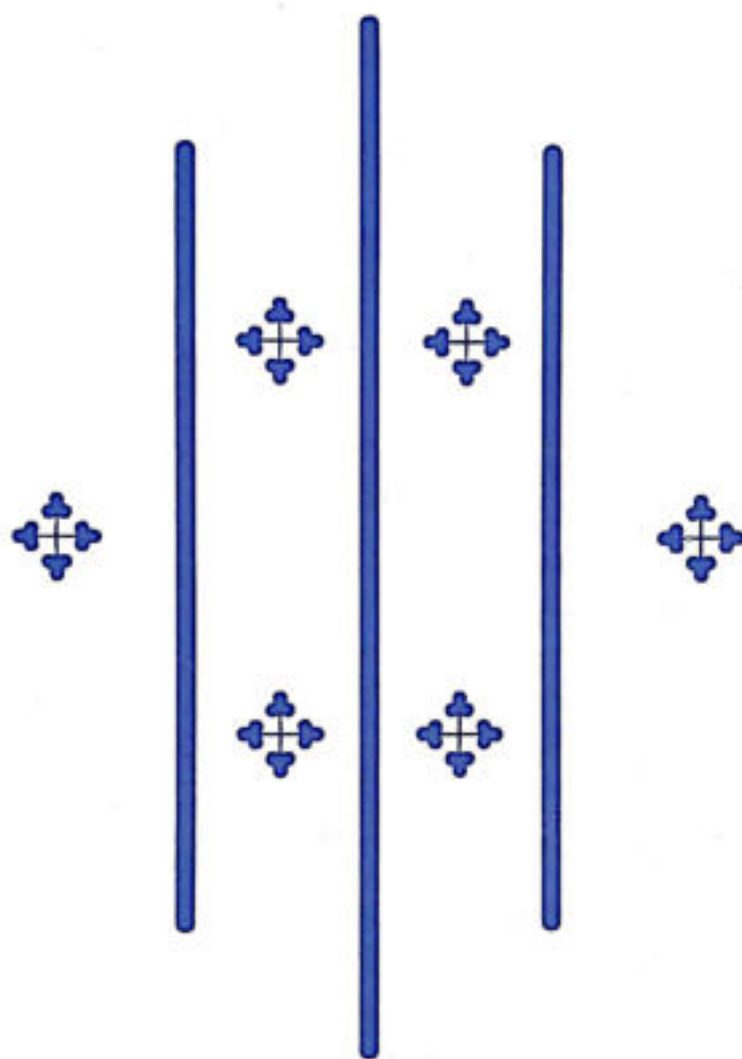
N. R. Book DISTRIBUTORS

3923/18, Kanhaiya Nagar, Trinagar, Delhi-110035

Phone : 7196269, 7198809

E-mail : nrbd@biotekbook.com

हार्दिक शुभकामनाओं सहित



परमजीत सन्धू इ० चर्कर्स
मायापुरी, नई दिल्ली

FOR PROJECT LOAN PROPOSAL SETTING UP OF INDUSTRIES



Contact :-

PROJECT & INDUSTRIAL CONSULTANCY PVT. LTD.

H-7, Hauz Khaz, New Delhi - 110 016

Ph. : 6565657, 6513972, 6868646

Fax : 6513972, 6960947

E-mail : projectandindustrial@yahoo.com.in

Bhiwadi : H-310A, "Hill View", Industrial Area, Phase - I, Bhiwadi (Alwar),
Raj-301019, Tel. : 01493-20471, 21345

Faridabad : 38, 1st Floor, Neelam Flyover, N.I.T., Faridabad, Haryana-121001

Gurgaon : I, Basement, Anand Ganga Complex, Alwar Road, Gurgaon
(Haryana)-122001

शिक्षा के भारतीयकरण की चुनौती

-डॉ. महेशचन्द्र शर्मा

किसी भी विषय का राजनीतिकरण उस विषय के सही परिप्रेक्ष्य को बदल देता है। इतिहास लेखन के विषय में जो बहस आज हो रही है, वह अकादमिक कम तथा राजनैतिक ज्यादा है। इस बहस की शुरुआत कांग्रेस एवं वामपंथी दलों ने की थी। उनका आरोप था कि भाजपा नीत राजग सरकार शिक्षा का 'भगवाकरण' कर रही है। एक राजनैतिक आरोप के माध्यम से बहस शुरू की गई। स्वाभाविक तौर पर भाजपा को इसका जवाब देना था। उन्होंने सवाल किया कि क्या शिक्षा का भारतीयकरण नहीं होना चाहिए? क्या पाश्चात्यकृत मैकाले शिक्षा को ज्यों की त्यों चलने देना चाहिए? तथाकथित भगवाकरण तो शिक्षा का भारतीयकरण है, यह वांछनीय है, अर्से से इसकी मांग होती रही है।

कांग्रेस व वामपंथियों ने आरोप लगाया, यह भारतीयकरण नहीं, यह तो शिक्षा का सांप्रदायीकरण है। क्या सांप्रदायीकरण किया जा रहा है, इसके बारे में उन्होंने कोई भी तथ्य सामने नहीं रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ जो धिसे-पिटे आरोप वे दशकों से लगाते रहे थे, उन्हीं को पुनः-पुनः दोहराया गया। निश्चय ही उथली राजनीति का यह एक घटिया उदाहरण था।

इस विषय पर संसद में बहस हुई तब भाजपा की तरफ से ये सवाल खड़े किए गए कि 'राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद' जिन पुस्तकों को अनेक दशकों से बच्चों को पढ़ा रही है, क्या वे समुचित हैं? इन पुस्तकों में राष्ट्रीय महापुरुषों के प्रति असम्मान सूचक संबोधनों का उपयोग किया गया, यथा महात्मा कबीर एवं गुरु नानक देव के लिए 'वह' तथा 'उसने' शब्दों का प्रयोग किया गया है।

भारत में आर्यों के आक्रमण का मुद्दा विवादास्पद है, अनेक नवीन अनुसंधानों एवं उत्खननों ने इस पाश्चात्य स्थापित मान्यता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अतः भारत पर आर्यों के आक्रमण विषय को

एक स्थापित सत्य के रूप में क्यों पढ़ाया जा रहा है? संस्कृत में 'आर्य' शब्द नस्ल या जाति सूचक नहीं बरन श्रेष्ठता सूचक है, यह बात इन पुस्तकों में क्यों नहीं है?

पाश्चात्यों की इस स्थापना का अकादमिक आधार चाहे जो हो, लेकिन साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने 'आर्यों के आक्रमण' के तर्क का भारत की आजादी के संदर्भ में दुरुपयोग किया था। उन्होंने भारत की आजादी पर सवालिया निशान लगाया था कि भारत की आजादी यानि किसकी आजादी? भारत नाम का न तो कोई राष्ट्र है न कोई समाज। भारत केवल भूगोल है। यहां पहले आर्य आक्रमण करके आए फिर यूनानी, शक, हूण आक्रमणकारी के रूप में आए बाद में मुगल, तुर्क, पठानों ने आक्रमण किया तथा अंत में अंग्रेज यहां पर आ गए, यहां तो सभी विदेशी हैं। कोई स्वदेशी समाज है ही नहीं, फिर किसकी किससे आजादी? यहां के मूल निवासी तो जंगलों में रहने वाली आदिवासी हैं। हम सब ने उन पर राज किया है। हमने तो सत्ता मुसलमानों से हथियाई थी, अतः तथाकथित भारतीय आजादी का वास्तव में कोई मतलब नहीं है। भारतीय राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है, अतः उन्होंने भारत को भौगोलिक 'उपमहाद्वीप' की संज्ञा दी।

क्या आजादी के बाद भी यह साम्राज्यवादी तर्क भारत की पाठ्यपुस्तकों में जैसे का तैसा रहना चाहिए? यदि तथाकथित 'आर्य' कोई घुमंतू जाति भी थी तो क्या इसका वर्णन समुचित प्रकार से नहीं होना चाहिए? राष्ट्र संज्ञा मानव की आदिम एवं घुमंतू स्थितियों में उत्पन्न नहीं हुई थी। राष्ट्र के रूप में भारत का स्थापित समाज वैदिक समाज है, जिसका क्रमशः बहुलतावादी विकास हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता पर अभी समुचित अनुसंधान बाकी है। क्या इन तथ्यों को साम्राज्यवादी लहजे में ही पढ़ाया जाना उचित है। क्या भारत की अकादमिक प्रतिभा इन तथ्यों के साम्राज्यवादी लहजे का निरसन नहीं कर सकती? निश्चय ही मुद्दा भावनाओं का

नहीं तथ्यों का है। इतिहास का लेखन इतिहासकार ही करेगा, मजहबी एवं पंथिक नेता नहीं, लेकिन गुरु तेग बहादुर के बारे में एक अपुष्ट विदेशी साक्ष्य सामने रख कर सभी भारतीय साक्ष्यों को दरकिनार करने वाली अकादमिक प्रतिभा को क्या कहें? गो-पूजक भारत देश के समाज को अंग्रेजों ने तो चिढ़ाने के लिए यह तथ्य परोसा था कि तुम्हारे पूर्वज आर्य गोमांस खाते थे। क्या समाज को चिढ़ाने वाले इस लहजे को अकादमिक तर्क कहा जाए? समाज अपने विकास की समुचित यात्रा करते हुए गो-पूजा के मुकाम तक पहुंचा होगा। उस मुकाम का सम्प्रेरक अनुसंधान करना क्या भारत की अकादमिक प्रतिभाओं का काम नहीं है?

भारत के पुराण साहित्य को काल्पनिक तो साम्राज्यवादी अकादमिकों ने घोषित कर ही दिया था। क्या आज भी हम उसी को दोहराते रहें? पुराण साहित्य का भी कोई इतिहास होगा। किसी पुराण की रचना कब हुई, क्यों हुई? उसके पात्रों की ऐतिहासिकता एवं साहित्यिकता का तथ्य आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा? क्या यह भारत के अकादमिकों का काम नहीं है? यदि अकादमिक जगत से इसकी अपेक्षा की जाए, तो कुछ गलत हो जाएगा? आजाद भारत के अकादमिक लोग साम्राज्यवादियों की जूठन ही अनंत पीढ़ियों को परोसते जाएंगे? क्या भारत का समाज अपने आज के भारत के अकादमिकों से यह अपेक्षा न करे?

बहु-उपासना पद्धतियों व दर्शनों वाले इस समाज का ताना बाना बुनने वाले महापुरुषों का दर्शन हमें साम्राज्यवादी क्यों करवाते, तो क्या आजाद भारत का शिक्षा पाठ्यक्रम भी इससे सूना रहना चाहिए? 'एकम् सद विप्राः बहुधा वदन्ति' एवं 'स्यादवाद' तथा 'अनेकांत' की अवधारणाओं ने भारत की बहुलतावादी एकात्म-संस्कृति का सृजन किया है। भारत की राष्ट्रीयता के बीज भारत के समाज में हैं, उसके लिए उसे सघ उद्घाटित पश्चात्य 'राष्ट्र-राज्य' की अवधारणा की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की सामाजिक बहुलता को संरक्षित करने के लिए भी स्वयं भारतीयता समर्थ है, उसे पश्चिम में जन्मी 'सेक्यूलरिज्म' अवधारणा की आवश्यकता नहीं है।

भारत की धार्मिकता ने यहां सामाजिक एवं पंथिक बहुलता को पनपाया। एकांतिक पंथिकता को भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया। भारत के संदर्भ में 'थियोक्रेसी' अप्रासांगिक अवधारणा है। इन तथ्यों को क्या समुचित अकादमिक अनुशासन में समाहित नहीं करना चाहिए।

किसी को चिढ़ाने एवं आहत करने के लहजे में अकादमिक तथ्यों को पेश करने में कौन सी विद्वता है? क्या परायेपन का भाव लेकर इतिहास लेखन को वस्तुनिष्ठ कहा जाना चाहिए। अपने समाज के गुण-दोषों का वर्णन क्या हम आत्मीय लहजे में नहीं कर सकते?

यह एक लंबी दास्तान है, लेकिन संसद में हुई बहस के बाद, कुछ अंशों पर समाज के विविध समुदायों से आपत्तियां उठीं। जिन बातों पर पहले ध्यान नहीं गया था, वे इस बहस के कारण उजागर हो गईं। परिणामतः एन सी ई आर टी ने कुछ अंशों को पाठ्यक्रम से निकालने की घोषणा कर दी। पाठ्यक्रमों से अंशों को निकालने की शुरुआत पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने की थी फिर उसका अनुसरण कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने किया तथा वही प्रक्रिया एन सी ई आर टी ने अपनाई। निश्चय ही यह अच्छी प्रक्रिया नहीं है। इसमें एक कृत्रिमता है। वास्तव में भारत के अकादमिक नेतृत्व को इन मुद्दों पर बहस करनी चाहिए थी। लेकिन बहस तो राजनीति वाले कर रहे हैं। जो वास्तव में एक राजनैतिक विचारधारा के पोषण के लिए, अकादमिक क्षेत्र का दुरुपयोग करना चाहते हैं।

द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चात्य साम्राज्यवाद दक्षिण एवं वाम की विचारधारा में विभक्त हो गया था। पश्चात्य मानसिकता के वामपंथी धड़े ने भारत के अकादमिक क्षेत्र को आप्लावित करने का अनअकादमिक कार्य किया है। आज निश्चय ही भारत की शिक्षा को पश्चात्यीकरण की गिरफ्त से मुक्त कर, 'भारतीयकरण' के परिवेश से युक्त करने की आवश्यकता है।

(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं सदन में भाजपा के मुख्य सचेतक हैं)

किस तरफ और किस तरह का इतिहास

—प्रो. जगमोहन सिंह राजपूत

स्कूल शिक्षा के कितने ही विशिष्ट आयाम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। पिछले दशक में बस्ते का बोझ, पाठ्यक्रम का दबाव और माता-पिता द्वारा थोपी जाने वाली इच्छाओं और अपेक्षाओं के संबंध में अनेक बार चर्चा होती रही है। पाठ्यक्रम की उपयोगिता, अनुकूलता तथा उसका देश और समाज के संदर्भों से जुड़ना शिक्षा नीति के अंतर्गत चर्चा में विशेष स्थान पाते रहे हैं। पाठ्यक्रम का लगातार नवीकरण शिक्षा व्यवस्था की एक सर्वमान्य प्रक्रिया है। 1988 में बने स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम तथा उस समय की पुस्तकों के नवीकरण की प्रक्रिया एन.सी.ई.आर.टी. ने इसी संदर्भ में 1999 में पुनः सक्रिय रूप से प्रारंभ की। शिक्षकों, शिक्षाविदों, पालकों तथा अनेकानेक अन्य वर्गों का एन.सी.ई.आर.टी. पर दबाव था कि पाठ्यक्रम को समयानुकूल बनाएं, पुस्तकें फिर से देखें और इस प्रक्रिया को शीघ्रतिशीघ्र पूरा करें। इसी आधार पर स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम की नई रूपरेखा पर एक परिचर्चा प्रपत्र बनाया गया जिसे पूरे देश के सामने रखा गया। तत्पश्चात् सारे देश में उस पर गहन विचार-विमर्श हुआ और उसी आधार पर नई रूपरेखा बनी। इसमें कक्षा एक से बारह तक के सारे विषयों को सम्मिलित किया गया। पाठ्यक्रम के बाद पाठ्यचर्चा तथा पुस्तक निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ, जो इस समय चल रहा है।

सारे देश में इस पर कई महीने से चर्चा हो रही है। लेकिन एक विशेष वर्ग ने, जो पाठ्यपुस्तकें लिखने की प्रक्रिया से (अब) जुड़ा नहीं है, अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की और अपनी चिंता और व्यग्रता को कुछ इस प्रकार की अभिव्यक्ति दी कि देश खतरे में है, इतिहास बदला जा रहा है। उन्होंने 'उन' पुस्तकों की आलोचना पहले ही प्रकाशित कर दी जो अभी लिखी ही नहीं गई हैं! पुस्तक लेखन के इतिहास में यह ऐतिहासिक घटना है।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रस्तुत स्कूल शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा पर आलोचना, चर्चा, परिचर्चा और

संवाद होना ही चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों की रुचि केवल विवाद में थी। चूंकि उन्हें वहां ऐसा कुछ नहीं मिला जो शिक्षा नीति 1986-92 के या संविधान और पंथ निरपेक्षता के विरुद्ध होता, अतः आलोचना की दिशा मोड़ दी गई और उसे पूर्ण रूप से राजनैतिक बना दिया गया। वहां पर भी जब जमीन खिसकती नजर आई तो अब वह व्यक्तियों की आलोचना के स्तर पर आ गए हैं। जिन लोगों ने और जिस संस्था ने रूपरेखा बनाई उन्हें कहा गया कि उसने यह सब सरकार राजनैतिक या अन्य संगठनों के कहने पर बनाई है। पूर्वाग्रह, आशंकाएं और आक्रोश सदैव ही सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उचित अभिव्यक्ति के शत्रु रहे हैं। उस स्थिति में तो कुतर्क पर आश्रित होना पड़ता है और कुछ लोग यही कर रहे हैं। उन्हें 'तालिबानीकरण' जैसे शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। पहले 'भगवाकरण' शब्द बूढ़ा गया था। देश ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब तालिबानीकरण है, जो प्रयोग करने वालों की मनःस्थिति को स्पष्ट करता है और जो स्वयं जनमानस द्वारा दुत्कार दिया जाएगा। फिर कोई तीसरा शब्द खोजना पड़ेगा।

ऐसी मनःस्थिति में उन्हें सच भी धुंधला दिखाई देता है। एन.सी.ई.आर.टी. जो कुछ कर रही है उसका प्रभाव शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ेगा, उसकी व्यवस्था पर पड़ेगा और कुल मिलाकर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। स्वार्थवश कुछ लोग परिवर्तन की इस प्रक्रिया में व्यवधान डालना चाहते हैं। उन लोगों के अनुसार शैक्षिक प्रगति की परिभाषा केवल यह है कि उन्हीं का वर्चस्व लगातार बना रहे, उन्हीं की इच्छानुसार सारे संस्थान चलें और जो उनके पीछे विनम्रतापूर्वक चलने को तैयार न हो, उसे देश के सामने पुरातनपंथी और प्रतिक्रियावादी घोषित कर दिया जाए। अंग्रेजी भाषा के अनेक समाचार-पत्रों का सहयोग इसमें उन्हें आसानी से प्राप्त हो जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एन.सी.ई.आर.टी. राष्ट्र द्वारा स्थापित संस्था है। उसका संपर्क क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। उसकी पुस्तकें लिखने के लिये लेखक, विद्वान और

अध्यापक सारे देश में उपलब्ध हैं। एन.सी.ई.आर.टी. ने तय किया कि केवल कुछ ही लोग इतिहास की पुस्तकें हमेशा न लिखते रहें, यह परिपाटी बदलनी चाहिए। अन्य लोगों को भी अवसर दिया जाये। इस विशाल देश में बुद्धि, बुद्धिमत्ता और विद्वानों की कमी नहीं है। लेकिन आलोचकों की धारणा है कि एन.सी.ई.आर.टी. का यही 'अपराध' है। उसने अन्य लोगों से पुस्तकें लिखवाने का साहस कैसे किया। उन्हें इस तथ्य से कोई सरोकार नहीं है कि पुस्तकें स्कूल के विद्यार्थियों के लिये लिखी जानी हैं। इस प्रक्रिया में विद्वानों का जुड़ना आवश्यक है, अपेक्षित भी है, परन्तु केवल इतना ही काफी नहीं है। पुस्तक निर्माण में हर स्तर पर अध्यापकों का जुड़ना भी उतना ही आवश्यक है। इस बार ऐसा ही किया जा रहा है और निश्चित ही यह देश के अध्यापकों को स्वीकार्य होगा और बच्चों के हित में होगा। पुस्तक निर्माण प्रक्रिया में सलाहकार समितियाँ, लेखक वर्ग, पुनरीक्षण समिति के सदस्य, संपादकगण सभी अपना योगदान करेंगे। यह सभी एन.सी.ई.आर.टी. में आकर अपना कार्य करते हैं। चिंतित वर्ग हर जगह यह घोषणा कर रहा है कि सभी कुछ 'गोपनीय' ढंग से हो रहा है और लेखकों के नामों की घोषणा नहीं की जा रही है। पिछले चालीस वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुस्तक निर्माण के पहले लेखकों के नामों की औपचारिक घोषणा करने की मांग उठी हो या उसकी आवश्यकता पड़ी हो। अतः इस बार ही ऐसा करने की कोई आवश्यकता एन.सी.ई.आर.टी. को नहीं लगती है। पुस्तकें कुछ महीनों में बाजार में उपलब्ध होंगी, उन पर वह सभी नाम जो होने चाहिए, होंगे। तब तक सभी को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रशंसकों को भी और आलचकों को भी। उसी स्थिति में लेखन से संबंधित सभी व्यक्ति अपना कार्य सुचारु रूप से बिना किसी व्यवधान के कर सकेंगे।

संसद के दोनों सदनों में शिक्षा में भगवाकरण पर चर्चा हुई। अधिकांश समय एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम की रूपरेखा की चर्चा रही और उसमें सबसे अधिक ध्यान इतिहास की पुस्तकों पर रहा। पुस्तकों के अंश उद्धृत किये गये और अनेक विद्वान सदस्यों ने अपनी-अपनी राय रखी। दिल्ली विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि कुछ अंश निकाल दिये जायें और जिन पुस्तकों में धर्मों

के संबंध में आपत्तिजनक सामग्री हो उन्हें प्रतिबंधित कर दिया जाये। यह प्रस्ताव तथा दिल्ली सरकार द्वारा कुछ अंश निकालने का आदेश एन.सी.ई.आर.टी. में भी आधिकारिक रूप से आया। एन.सी.ई.आर.टी. ने तब तक कोई अंश निकालने की संस्तुति नहीं की थी। जो कुछ बाद में किया गया वह इतिहासकारों से संपर्क कर उनकी राय लेकर किया गया। इस निर्णय का एक प्रतीकात्मक परन्तु गहरा महत्व है जो देश हित में है, देश के भविष्य के हित में है और जिसे पूर्वाग्रहों से परे रहकर समझने की आवश्यकता है। कुछ गिनेचुने लोग ऐसा नहीं कर पायेंगे परन्तु सारा देश इसे समझ रहा है और स्वीकार कर रहा है। कुछ अनिच्छापूर्वक ही सही, 'यू-टर्न' करने के लिये स्वयं को तैयार कर चुके हैं, बाकी शायद कर रहे हैं।

इस समय विश्व के अधिकांश देशों के सामने तीन संकट स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं : आर्थिक संकट, प्रगति की अवधारणा का संकट तथा 'किसी न किसी' प्रकार के मूल्यों का संकट। देश विशेष के सामने अन्य संकट भी हो सकते हैं। उन सभी के समाधान में शिक्षा और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा हर क्षेत्र में आवश्यक मानी जा रही है। लेकिन हमारे देश में यह स्वयं में एक बड़ी समस्या है। शिक्षा को प्रगति और विकास में योग देने योग्य बनाने के लिये उसमें सतत् परिवर्तन की आवश्यकता को सभी स्वीकार करते हैं। पाठ्यक्रम बदलते हैं, पुस्तकें बदलती हैं इतिहास की पुस्तकें और इतिहासकार भी बदलते हैं, इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को भी कष्ट क्यों होना चाहिए। यह बात सामान्य तौर पर भी समझ से परे है।

शिक्षा का उत्तरदायित्व है कि वह देश के लिये ऐसे नागरिक तैयार करे जो अपने राष्ट्र को जानें और समझें। वह अपने देश का इतिहास भी जानें, उसके वर्तमान को समझें और इस जानकारी तथा समझ के आधार पर भविष्य में अपने योगदान की व्यावहारिक तथा तथ्यपरक संकल्पना करें और अपने में उसे साकार रूप देने की क्षमतायें उत्पन्न कर सकें। इतिहास से वह अपने देश के वैभव, शौर्य, चिंतन, शोध, ज्ञानार्जन, वाङ्मय, संस्कृति तथा उसके विकास की गाथा से परिचित हों। यह परिचय उनमें संवेदनशील वर्षों में हीनता की भावना पैदा करे

और अपने देश के महापुरुषों के प्रति असम्मान की भावना बढ़ाये-ऐसा इतिहास कुछ लोगों को प्रिय हो सकता है परंतु देश के जनमानस को स्वीकार्य नहीं होगा। कितने ही दशकों से हर प्रकार की आवाजें उठती रही हैं परंतु उन्हें अनसुना किया जाता रहा। जो लोग एक तरफ यह दुहाई देते रहें कि इतिहास को मिथक नहीं बनने देंगे वही आज मिथकों के लिये प्रमाण मांगते हैं। वह दूसरे इतिहासकारों के विचारों को बच्चों के समक्ष नहीं आने देना चाहते हैं। सारा इतिहास कुछ गिने-चुने लोगों की चुनी विचारधारा के अंतर्गत ही रहे और बाकी सभी विचारों, तथ्यों और विश्लेषणों को परे कर दिया जाये, ऐसा अब होने वाला नहीं है। यही विषाद की जड़ और विवाद का स्रोत है।

किसी भी विषय के पाठ्यक्रम बनाने वालों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले के घर के वातावरण तथा स्कूल के वातावरण में एक प्रगाढ़ संबंध होता है। ऐसा न होने पर बच्चों के मन-मस्तिष्क में अनावश्यक द्वंद्व उत्पन्न होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक कम करना चाहिए, विशेषकर स्कूल के प्रारंभिक वर्षों में। यहां पर यह तथ्य भी जानना आवश्यक है कि भारत का समाज धर्म पर आस्था रखता है और भारत राष्ट्र पंथ निरपेक्ष है। इन दोनों में विरोधाभास नहीं है। सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म समादर से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, इतिहास को भी नहीं और इतिहासकारों को भी नहीं। कोठारी आयोग (1964-66) ने इसे समझा और इसका विश्लेषण किया। आयोग का मत था कि समाज में समरसता आवश्यक है और सब धर्मों के स्वीकार्य (टालरेंट) अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि सब (धर्मों के) लोग सौहार्दपूर्ण ढंग से साथ-साथ रह सकें और एक-दूसरे को और अच्छी तरह समझ सकें। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह धर्म के बारे में जानकारी की अनुशंसा कर रहा है, धार्मिक शिक्षा की नहीं। फरवरी, 1999 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थाई समिति ने मूल्यों की शिक्षा पर संसद में रखे गये अपने प्रतिवेदन में ऐसी ही सिफारिश की। एन.सी.ई.आर.टी. ने तदनुसार यह बात अपनी पाठ्यक्रम की रूपरेखा में कही। इससे भी आलोचक वर्ग विचलित हुआ, आध्यात्मिकता तथा धर्मों के बारे में जो कुछ अनेक आयोगों, मनीषियों ने कहा उसे भुला दिया गया और एन.सी.ई.आर.टी. को कटघरे

में खड़ा करने का प्रयास किया गया। यहां तक आरोप लगा कि एन.सी.ई.आर.टी. ने 'धर्म निरपेक्षता' को 'पंथ निरपेक्षता' में बदल दिया है। यह चिह्नित आलोचक मूल्यों की शिक्षा, धर्मों के बारे में जानकारी और इतिहास, तीनों को पूर्वाग्रह जनित दृष्टि से देखते हैं। क्या वह चाहते हैं कि जो लोग इस देश में पूज्य हैं, जो अपने त्याग और बलिदान के लिये जाने जाते हैं, नई पीढ़ी में उत्साह, और देशभक्ति की भावना जगाते हैं, उसे सुदृढ़ करते हैं और 'कारगिल' जैसे अवसरों पर देश के लिए हंसते-हंसते बलिदान करने की शक्ति देते हैं, उन्हें उसी ढंग से प्रस्तुत न किया जाये। भगतसिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान कुछ लोगों के लिये षड्यंत्रकारी या आतंकवादी थे (या हैं) परंतु इस राष्ट्र के लिये तो वह सदा स्वतंत्रता सेनानी ही थे और रहेंगे। इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा, कुछ इतिहासकारों के 'सरकारी स्रोत' कुछ भी क्यों न कहते हों। इसीलिए अन्य स्रोतों को भी समझना होगा, उद्धृत करना होगा। केवल यही कहा जा रहा है और यह सहज सुझाव एक वर्ग विरोध में अप्रत्याशित असहजता को जन्म दे रहा है।

कुछ लोगों का विश्वास है कि देश और समाज के हित की धिंता करना केवल उन्हीं का अधिकार है जिन्होंने अपने को 'प्रगतिशील' तथा बाकी सभी को 'पुरातनपंथी' घोषित कर दिया है। अनेक वर्षों तक संस्थाओं पर एकाधिकार तथा एक प्रकार की विचारधारा का पोषण कर, बाकी सबको अलग रखकर उन्होंने संभवतः 'परिवर्तन' शब्द को ही भुला दिया है। चिह्नित प्रगतिशीलों के लिये विरोध करना ही प्रगतिशीलता की निशानी है। असहमत होकर ही प्रचार माध्यमों में स्थान मिलता है, खबर बनती है, लोग जाने जाते हैं और उनमें से कुछ अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। वह प्रगतिशील ही क्या जो सदा खबरों में रहने का प्रयत्न न करे! इसके लिये आलोचना के बिंदु ढूंढ लेने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। इन्होंने स्वयं अपने एक संप्रदाय का निर्माण किया, उसका पोषण किया, और आज जब वह विघटित हो रहा है तो वे यह बाकी सभी को 'सांप्रदायिक घोषित कर रहे हैं। इतिहास को विचारधारा प्रचार का साधन बनाने वाले आज मिथक को इतिहास बनाने का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। शायद वे जाने-अनजाने स्वयं में एक मिथक बनने का प्रयास कर रहे हैं।

With Best Compliments



JUGEL WADHWA & CO.

Advocate

RESI. : H-3, IIND FLOOR, MAIN ROAD,
RAJOURI GARDEN, NEW DELHI-110017

PH. : 5166254, 5166256 (OFF.)
MOBILE : 9810036560

शिक्षा का भारतीयकरण

-डॉ० महेश चन्द्र

स्वामी विवेकानन्द ने एक ऐसी शिक्षा की संकल्पना की थी जिससे "चरित्र निर्माण हो, मस्तिष्क के सामर्थ्य में वृद्धि हो, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो"। इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए स्वामी जी ने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति अपनाने पर बल दिया जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच पर्याप्त व्यक्तिगत सम्पर्क रहता था जिसका आजकल सर्वथा अभाव है।

वर्तमान शिक्षा पद्धति को सामान्यतः जानकारी के संप्रेषण की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें मानवीय मूल्यों और चरित्र विकास की अनदेखी होती है। इसीलिए स्वामी विवेकानन्द ने वर्तमान दुरावस्था के विषय में उल्लेख करते हुए दिशा बोध कराया था कि "शिक्षा जानकारी मात्र नहीं है जो किसी के मस्तिष्क में भर दी जाए और वही जीवन भर अनुपयोगी पड़ी सड़ती रहे। हमें जीवन निर्माण, मानव निर्माण, चरित्र निर्माण और विचारों का स्वांगीकरण होना ही चाहिए। यदि शिक्षा और सूचना समरूप होते तो पुस्तकालय विश्व के सबसे बड़े चिंतक होते और विश्वकोश ऋषि होते"।

इस प्रसंग में श्री शंकर राव चव्हाण की अध्यक्षता में गठित समिति ने, जो मूल्य-आधारित शिक्षा पर थी, अपना प्रतिवेदन राज्यसभा को 26 फरवरी 1999 को प्रस्तुत किया। उसमें 5 अनिवार्य मूल्यों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया। वे हैं सच्चाई, न्यायसंगत आचरण, शान्ति, प्रेम और अहिंसा। इन्हें किसी भी मूल्य-आधारित कार्यक्रम का प्राण बताया गया जो शिक्षा में आवश्यक हैं।

विद्वानों का यह भी मत है कि भारतीय संदर्भ में यह अब बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपने किशोरों, किशोरियों और युवाओं को प्राचीन भारतीय चिन्तकों, विचारकों और मनीषियों के मौलिक आविष्कारों और अनुसंधानों का भी ज्ञान कराएं जिनके कारण मानव को आगे बढ़ने और शान्ति पूर्वक स्वस्थ जीवन बिताने का आधार सुलभ हुआ है।

उदाहरणार्थ शिक्षा में यह पढ़ाया जाये कि भारतीय विचारक महर्षि कणाद (कणों से पेट भरने वाला) ने अणु और परमाणु की खोज आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व की। उन्होंने कहा था - 'अणु ही ब्रह्माण्ड की मूल सत्ता है' उनके वैशेषिक दर्शन का ज्ञान कराना आवश्यक क्यों

नहीं होना चाहिए? अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व भारतीय ज्योतिर्विद आर्यभट्ट (प्रथम) ने 'आर्य भट्टीयम्' में लिखा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। उनके ग्रंथ में अनेक गूढ़ बातें भरी हुई हैं। ऐसे विलक्षण ग्रंथ को विज्ञान के उच्चस्तरीय पाठ्यक्रमों में क्यों नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? वराह मिहिर ने अपने दुर्लभ ग्रन्थ 'पंच-सिद्धान्तिका' में गणित ज्योतिष का विवेचन किया है जो बेजोड़ है। अपने ऐसे अनुसंधानों को नकारना अथवा महत्त्व न देना शिक्षा की भारी कमी है, जिसे दूर करना ही पड़ेगा। अरबवासी गणित को 'इल्म-ए-हिंदसा' अर्थात् हिंदुस्थान की विद्या कहते थे, क्योंकि शून्य का और दशमलव प्रणाली का ज्ञान भारत से ही विश्व को मिला। आर्यभट्ट (प्रथम) ने ज्यामितीय विषयों का विवेचन किया है जिसमें त्रिभुजों, चतुर्भुजों और वृत्तों के क्षेत्रफलों और ठोसों के आयतन के सूत्र दिए गए हैं।

उन्होंने घ (पाइ) का मान भी बताया है। शल्ब प्रमेयों का ज्ञान हमें अब से 5000 से 6000 वर्ष पूर्व हो गया था। कालान्तर में बोधायन, कात्यायन और आपस्तम्ब ने उन्हें सूत्रों के रूप में निबद्ध किया।

हड़प्पा (अब पाकिस्तान में) में सिलाई की सुइयां मिली हैं। 4, 3.93 और 3.85 इंच लम्बे धातु के कौटे भी मिले हैं जो दोनों सिरों पर नुकीले थे। सैंधव सभ्यता (हड़प्पा-मोहन-जोदड़ो) के जिसे लगभग 8,000 से 10,000 वर्ष पुरानी आर्य सभ्यता ही माना जाने लगा है, लोगों को लुक या काच बंधन कर्म (ग्लेज करने) की कला का ज्ञान था। ऐसे असंख्य तथ्य हैं जिन्हें हमारी पीढ़ियों को जानना चाहिए।

जब ये सब तथ्य शिक्षा में शामिल होंगे और प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कराया जाएगा, साथ-साथ शिक्षा में नैतिक मूल्य और मानवीय मूल्य भी स्थान पा लेंगे तब माना जाएगा कि शिक्षा उद्देश्य-परक हुई है। वही वह सोपान होगा जिसे शिक्षा का भारतीयकरण कहा जाएगा।

वैज्ञानिकता में देवनागरी लिपि का मुकाबला विश्व की कोई लिपि नहीं कर सकती। संस्कृत भाषा के शब्द अपने भीतर अध्यात्म और विज्ञान समेटे हुए हैं। शिक्षा के भारतीयकरण का एक कदम यह भी होगा कि इन का प्रचलन और अध्यापन तीव्र गति से बढ़ाया जाए।

-शेष पृष्ठ 30 पर

With Best Compliments

MANOHAR CHIT FUND

&

FINANCEIRS (P) LTD.

**Manohar House, Hudson Line,
Delhi-110009**

Ph. : 7214907, 7432044

Fax : 7466015

TRUST MANOHAR GROW MORE

शिक्षा का स्वदेशीकरण

जीवन का दूसरा नाम परिवर्तन है। यह एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो हमारे सभ्यता एवं संस्कृति के सभी पक्षों जैसे आधार-विचार, मूल्य, विकास, आदि में देखा जा सकता है। शिक्षा जो समाजीकरण की सबसे प्रबल अभिकरण है, इससे अछूती नहीं है। आदिम सभ्यता से चलकर औद्योगिक अवस्था तक शिक्षा का समाजीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। अंतर सिर्फ इतना है कि प्राचीनकाल में परिवार का शिक्षा पर वर्चस्व था, आज आधुनिक समाज में परिवार की जगह आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों का चलन है। हालांकि इन शिक्षण संस्थाओं की अवधारणा प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित 'गुरुकुल व्यवस्था' की है। समग्र रूप से यह सत्य है कि शिक्षा जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है। परन्तु सामाजिक प्राणी के निर्माण की गाथा समय, स्थान एवं संस्कृति सापेक्ष है।

भारत को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए आज 54 वर्ष हो चुके हैं जिसमें भारत ने तथाकथित आर्थिक उन्नति प्राप्त की है। आज हम अंतरिक्ष में जाने में आत्म निर्भर हैं, सौ करोड़ जनसंख्या का पेट भरने में भी सफल हैं, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार हैं, परन्तु क्या कभी गौर किया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्या खोया व क्या पाया है। शायद नहीं! अगर ऐसा किया गया होता तो भारतीय समाज आज के वैज्ञानिक युग में उत्तर-दक्षिण, हिन्दु-मुस्लिम, ऊँच-नीच आदि विवादों से कहीं ऊपर उठ गया होता।

शिक्षा का क्षेत्र, प्रकृति और स्वरूप आज भी मैकाले की शिक्षा नीति से कहीं अलग नहीं। वेष भूषा से भारतीय किन्तु आचार-विचार से अंग्रेज शिक्षार्थियों की संख्या जंगल में लगी आग की तरह फैलती जा रही हैं। केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने ईसाई मिशनरियों की ही तरह अंग्रेजी सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में पिछले 54 वर्षों में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिक्षा का वर्तमान अभिप्राय आई- आई- टी- एवं आई- आई- एम- की सफलता से है। भारत सरकार द्वारा पोषित इन संस्थानों से उत्तीर्ण ये युवागण बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सुरताल पर थिरकते, भारतीय उद्योग जगत एवं बाजार का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जनमानस का वित्तीय शोषण करने में लगे हैं। वैश्वीकरण के इस माहौल में अपना देश, अपनी माटी, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति आदि की बातें करना या तो फूहड़पन है या फिर दक्षिणपंथी विचारधारा को फैलाने का षड़यंत्र। पं- जवाहरलाल नेहरू ने नव स्वतंत्र भारत में अफसरशाही की बागडोर अंग्रेजी भाषियों के हाथ सौंपी ताकि अन्तराष्ट्रीय जगत में भारत का

नाम हो। विभिन्न देशों से तालमेल रखने वाले, विभिन्न राष्ट्रों की संस्कृति को समझने में सफल रहे ये अफसरगण भारतीय जनमानस को समझने में विफल रहे। गाँवों में हल चलाता भाग्यवादी किसान, सरकार द्वारा बनायी लाभकारी नीतियों को जानने तक से वंचित रह जाता है। दो प्रतिशत अंग्रेजी अखबार पढ़ने वाले लोग शहरों में, वातानुकूलित विश्वविद्यालयों, आयोगों आदि में बैठकर सतही सर्वेक्षण के आधार पर सुदूर झारखण्ड के गाँवों में ओलचिकी लिपि तथा संथाली भाषी के लिए शिक्षण पाठ्यचर्या तथा सामग्री का निर्माण करते हैं। 'डिस्कवरी' तथा 'नेशनल ज्योग्राफिक चैनल' जैसे उपग्रहीय चैनल देखकर आज हम भारतीय संस्कृति को समझ रहे हैं। गाँवों को 'कंट्रीसाइड' बताने वाले आज संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य अन्तराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय गरीबी एवं संस्कृति पर व्याख्यान दे रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय पर किए जा रहे करोड़ों रुपये के व्यय का घरम सत्य क्या है? उत्तर सरल है, प्रोफेसरों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय मंचों पर 'आर्य गोमांस खाते थे' तथा 'आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे' की अवधारणा का पोषण करना। इतिहास के अतिरिक्त राजनीतिशास्त्र में भी ये पीछे नहीं। विश्व की सबसे बड़ी गैर सरकारी संगठन 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ' को यह नाजीवादी मानते हैं। चिन्ताजनक बात है इन प्रमुख विश्वविद्यालयों में इन प्रोफेसरों के प्रिय छात्रों की शिक्षक पदों पर नियुक्ति जो भविष्य में भ्रामक अवधारणों को स्वर देता रहेगा।

आज जब सरकार शिक्षा को समाज के हर वर्ग एवं तबके से जोड़ते हुए, शिक्षा को पुनर्परिभाषित करते हुए शिक्षा का देशीकरण करने में लगी है तो इस शुभ बेला में विपक्षी राजनीतिक दलों का हुजूम एवं तथाकथित अंग्रेजीशुद्ध धर्मनिरपेक्ष विद्वत्जन इसे 'शिक्षा का भगवाकरण' कह इसे नाकाम करने पर जुटे हुए हैं। वोट बैंक की राजनीति सत्य को सत्य कहने से इन्हें रोक रही है। लेकिन सूर्य की रोशनी को कौन रोक सकता है। आज आवश्यकता है कि हर एक विद्यार्थी विशेषकर विश्वविद्यालय छात्र जिनके जिम्मे देश का भविष्य है, 'शिक्षा' में किए जा रहे सुधार पर गंभीरतापूर्वक सोचे और एकजुट होकर छद्म बुद्धिजीवियों का पर्दाफाश करे।

आज पूरे देश में विपक्षी दलों एवं तथाकथित धर्मनिरपेक्ष विद्वानों द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार इतिहास में व्यापक फेरबदल कर हिन्दू धर्म का इतिहास विद्यालयों में पढ़ाने जा रही है। इतिहासकार का यह दायित्व है कि देश के इतिहास को इस प्रकार रचे कि वर्तमान अपने

इतिहास पर गौरवान्वित हो। परन्तु भारत में शायद इस मर्यादा का निर्वाह इतिहासकारों ने नहीं किया। आर्यों को विदेशी तथा द्रविड़ को स्वदेशी बताकर, उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के लोगों में वैमनस्य पैदा किया। हिन्दुओं के आद्यपिता आर्यों द्वारा गोमांस भक्षण को इतिहास में महिमामंडित कर बहुसंख्यक हिन्दुओं के मन में वितृष्णा को जन्म दिया। इन विषयों पर साक्ष्य के अभाव में विचारधारा में फर्क माना जा सकता है परन्तु ऐसे साक्ष्यों के होते हुए जिसमें सिख गुरुओं को धर्म की रक्षा करने वाला, जनता में भाईचारा बढ़ाने वाला माना गया है के बावजूद एन-सी-ई-आर-टी-की इतिहास की पुस्तक में गुरु तेगबहादुर को लुटेरा कहा गया है। आखिर बिगत 54 वर्ष में पढ़ाया जानेवाला इतिहास राष्ट्र को किधर ले जाना चाहता है। अगर इतिहासकार से इस बाबत प्रश्न पूछा जाता है तो प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चन्द्रा इसे अनुवाद की भूल कहकर मुकर जाते हैं तथा विख्यात इतिहासकार के-एम-श्रीमाली कहते हैं कि इतिहास तो साक्ष्य का विवरण मात्र है। इतिहासकार का दायित्व यह नहीं है कि वह समाज में आदर्श का निर्माण करने के लिए सही इतिहास रचे? आखिर इससे शिक्षा का मूल उद्देश्य 'वैज्ञानिक दृष्टि' का हनन भी तो होता है। इस संदर्भ में ग्यारहवीं कक्षा के लिए तैयार की जानेवाली 'प्राचीन इतिहास' के लेखकों डा० वर्मा तथा डा० माखनलाल को उन्होंने आनन-फानन में विश्व हिन्दू परिषद का इतिहासकार बता डाला।

आवश्यकता है आज हम युवाओं को उन तथाकथित इतिहासकारों से यह प्रश्न करने की कि अगर बाबर के बाद उनके पुत्र हुमायूँ, पौत्र अकबर, प्रपौत्र जहाँगीर एवं उनके बाद शाहजहाँ, औरंगजेब को जब भारत का निवासी कहा जाता रहा है विदेशी नहीं तो आज बहुसंख्यक हिन्दुओं से बसे इस भारत के आद्य पिता आर्य के मूल निवास को कटघरे में खड़े करने की आवश्यकता क्यों पड़ी।

आज शुद्धिकरण की बात घली है तो भगवाकरण कहा जा रहा है। शायद ठीक ही कहा जा रहा है क्योंकि शुद्धि एवं पवित्रता का प्रतीक भगवा ही तो है। आज हमें ऐसे इतिहास की आवश्यकता है जिसमें देशी राजाओं की शौर्य गाथा हो जिससे हर युवा में देश के प्रति देशभक्ति का संचार हो। भगवान राम का केवट तथा सबरी से संबंध को बताए जाने की आवश्यकता है ताकि जाति-भेद समाप्त किया जा सके। संस्कृत भाषा जो द्रविड़ भाषाओं के मूल में है वेदों की वाणी रही है। संस्कृत के प्रयोग द्वारा उत्तर-दक्षिण भाषाओं में मेल बढ़ेगा। भाषा-संघर्ष पर रोक लगेगी। इतिहास का लेखन ऐसे आदर्श के साथ हो जिससे देश की समस्याओं का समाधान भी हो सके।

उच्च शिक्षा जो अवधारणाओं पर तर्क-वितर्क तथा नव निर्माण एवं खोजपरक दृष्टि का पर्यायवाची है, के सामने

अलभ्य, अपूर्व वैदिक ज्ञान को रखने की आवश्यकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संदर्भ में विश्वविद्यालयों में विभिन्न धर्मों के बारे में ज्ञान, ज्योतिषशास्त्र तथा संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार का जिम्मा उठाया है जो उपयुक्त एवं समीचीन है। इसे भी 'शिक्षा का भगवाकरण' कहा जा रहा है।

धर्म का प्रभाव सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ता है। अतः धर्म के सामाजिक स्वरूप पर विचार-विमर्श करना बेमानी नहीं है। विश्व के तमाम विश्वविद्यालयों में विशेषकर शिकागो, स्टैंडफोर्ड, पैसिलवेनिया आदि में धर्मशास्त्र से संबंधित एक अलग विभाग ही है। भारत में ऐसी शुरुआत करने पर विपक्ष, विपक्ष बने रहने के लिए विरोध कर रहा है।

तथाकथित धर्मनिरपेक्ष विद्वानों की दूसरी शिकायत विश्वविद्यालयों में शुरू की जानेवाली 'ज्योतिषशास्त्र' की पढ़ाई से है। 'ज्योतिषशास्त्र' भारतीय ज्ञानगंगा की मंजूषा की अपूर्व निधि है जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है। किसी भी भाषा का शायद ही कोई अखबार हो जिसमें राशिफल ना छपता हो। शायद ही कोई देश हो जो ग्रह-नक्षत्र का अध्ययन ना करता हो। तथाकथित विद्वानों ने तो ज्योतिषशास्त्र को विज्ञान मानने तक पर आपत्ति कर दी है। आप उनसे पूछिए कि क्या अंग्रेजी चिकित्सा शास्त्र, विज्ञान है जिसमें एक ही प्रकार के सर्जरी से कोई रोगी स्वस्थ हो जाता है और कोई स्वर्ग सिंधार जाता है। अगर इस विज्ञान में शुद्धता तथा वैधता का निर्धारण संभव नहीं तो ज्योतिषशास्त्र पर यह आरोप क्यों लगाया जाता है। विज्ञान का आधार अंतर्वस्तु नहीं वरन् कार्यपद्धति है जिसका निर्वाह ज्योतिषशास्त्र में किया जाता है।

भारत की पहचान संस्कृत से जुड़ी हुई है। सदियों से भारत सहित विश्व की कई भाषाओं को संस्कृत ने अपने शब्द व व्याकरण से समृद्ध किया है। विद्वानों ने इसे स्वतंत्र भारत में अव्यवहारिक तथा मृत भाषा घोषित कर किनारा किया। यह राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान था। राजभाषा निर्धारित करने वाली समिति में बाबा साहेब आंबेडकर ने संस्कृत का समर्थन किया था। इस बात का प्रमाण आज उस समिति के एकमात्र जीवित सदस्य बी-पी-मौर्या से प्राप्त किया जा सकता है जिन्होंने संस्कृत का विरोध किया था, जिसपर आज भी उन्हें अफसोस है। अगर ब्रिटेन फ्रेंच को त्यागकर अंग्रेजी तथा इस्पायल अंग्रेजी को त्यागकर रातोंरात हिब्रू अपना सकता है तो भारत में कैसी देरी। संस्कृत को उसका उच्च स्थान अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

तमाम आरोपों तथा प्रत्यारोपों से विचलित हुए बिना सरकार, विद्वतजन समाज सुधारकों आदि का यह नैतिक तथा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि शिक्षा की अंतर्वस्तु तथा कार्यपद्धति में सुधार लाकर राष्ट्रीय नवनिर्माण को गति दें।

SITUATION TO BE TACKLED WITH A HOLISTIC PERSPECTIVE

SEMINAR ON "ECONOMIC REHABILITATION OF DISPLACED TRIBALS"

The seminar on "Economic Rehabilitation of Displaced Tribals" including workshop of tribal students was organised by Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, Orissa with the assistance and support of Ministry of Tribal Affairs, Govt of India at CYSD Hall, Bhubaneswar on 18, 19 & 20, November, 2001. The primary thrust of the seminar was to deliberate on the afore-said topic and to disseminate knowledge on the nuances of various issues concerning the tribal displacement from the pristine natural setting (obviously, their source of sustenance), so as to enable the government to formulate strategies concerning the core issue of tribal development. There were about 103 number of participants from Orissa and other states who participated actively for the three-day long deliberation and offered some meaningful suggestions.

The seminar was inaugurated by Sri Jual Oram, Minister, Tribal Affairs, Govt. of India on 18th Nov. 2001. In course of his inaugural speech Sri Oram, while addressing the core issue of tribal displacement on the occasion of various developmental initiatives, enthused the delegates to meditate and mull over the different aspects of tribal development. Sri Oram wanted the situation to be tackled from a holistic perspective. He insisted upon the cause of a sustainable development. For him, the tribals represent a distinct ethnic group with a well-defined socio-cultural heritage (the Little Tradition, as the sociologists say) which must be great tradition and he wanted that there should be more of meaningful interaction between the two traditions, while championing the cause of a prosperous, resurgent and developed India. As chief speaker in the Inauration, Sri P. Suryanarayan Suri, ABVP Tribal students work pramukh, explained the

necessity of ABVP to undertake such a social and economic subject in its priority basis activity and the challenges on tribal community vis-a-vis national interest, in an excellent way. Dr Kshit Bhusan Das, the director of the programme pointed at the core issue in clear and succinct terms and he insisted upon an economic solution to the issue of displacement and rehabilitation. He urged upon the delegates to cogitate upon the concept of "fair compensation" and to set a fair compensation package for future assessment and implementation.

The topic of discussion in the first technical session was "Law and Method Regarding Displacement" Prof Samson Maharana, Professor of commerce, Utkal University chaired the session and the Key-note address was given by prof L.K. Mahapatra, former Vice-Chancellor of Utkal University and an Anthropologist of international repute. Quoting profusely from the Ramayana, the mahabharat and citing references from the Jagannath cult, Prof Mahapatra presented a comprehensive survey of the tribal situation from time immemorial. He also pointed at the Mohenjodaro populace, the Aryan invasion, the report presented by Megastheness, Huen Tsang and Alberuni, submitted the historical account of tribal culture and tradition. The tribals, according to Prof. Mahapatra, represent a basic ingredient of Indian Socio-cultural past and any planning measure contravening their interests should not be undertaken. He gave a detailed analysis of the tribal displacement of account of Machkund Dam and Hirakud Dam, Upper Kolab and Indravati Dam and Irrigation projects and solicited the cause of a pragmatic political, bureaucratic will and concern to meet the situation. The refugees, according to him, get a better deal

With Best Compliments From :



PRINCE POLONIA

(Luxury Hotel)



 **pol inter**

*Manufacturers & Exporters of all kinds of
Readymade Garments*



PRINCESS BEAUTY PARLOUR & SALOON

with Ultramode Gadgets & Shehnaz Herbal Trained Staff



Princess CYBER CAFE-COFFEE SHOP



VISIT US AT :

HOTEL PRINCE POLONIA

2325-26, Tilak Gali, Paharganj, New Delhi-110055

Tel. : 3511930, 3511931, 3511932, 3511933 Fax : 3557846

than the displaced tribals. He insisted that the oustees deserve monetary compensation along with the national price for their lost land and other life-sustaining resources. Citing references to the World Bank-ordained Rehabilitation package, he highlighted the concept of "Replacement value" and wanted the project benefits to be shared by the people, who sacrifice their present, past and future for the said venture".

Dr A. B. Otta, Head, Dept. of Anthropology, S. B. women's college, Cuttack presented a thought-provoking paper entitled "Adverse effects of development projects on the displaced Tribals". In his paper, Dr Otta reflected upon the issues of marginalisation and social disarticulation caused there of due of the mega-project. He also presented a number of pragmatic suggestions and advocated the cause of converged developmental projects, area-specific economic rehabilitation, minimised development and peoples participation. He wanted that a displaced person-specific strategy with a concrete rehabilitation action plan should be mooted out, through mutual consent, much before the implementation of any plan.

Dr. S. Giri Rao, of Berhampur University narrated his painful experience in the Mudulipara Tribal Area and said that rehabilitation is done for the name sake. For example T.V. sets, video sets and even computers have been provided, without any provision for electricity. He wanted that there should be total rehabilitation. Dr. Nishamani Kar, Reader in English, P.N. College Khurda, insisted that socio-cultural rehabilitation must be persued along with economic rehabilitation. The chairman, Prof. Maharana Summed up the discussion and suggested that there should be complete rehabilitation. He said that the tribals live as a unit and therefore they must be rehabilitated as a group and not as individuals.

THE SECOND TECHNICAL SESSION was on "Fair compensation" Dr. A. B. Otta chaired the session and Prof. Banikanta Mishra, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar presented the key-note address. Based on his international exposure, Prof Mishra insisted on Right compensation. He said that before the implementation of any project, a trust involving the local people must be set up, which should look into various aspects of compensation and rehabilitation measures. He wanted that a considerable part of the profit accruing from the project should be spent on the peripheral development of the project. Since it ordains a question of the displaced people, it should rather be a moral obligation of the project management to look after the people, so affected by the said venture. He pleaded in favour of the Pro-active initiatives by the local NGOs and Social activists.

Dr. Ratikant Nanda, Reader in Commerce S.C.S. College, Puri, stressed that loss to be borne stoically by the affected people. He said that the cause of development cannot be sacrificed as we are to march with the global trend, but at the same time the affected people must be given a human deal. There should be proper communication and interaction between the people, who sacrifice and the local authorities, lest it should lead to a breach in social harmony, he said. 'Development for All' should be the motto. Ms. Sunita Lath, All India Secretary, ABVP, Sri Sanjay Das from Rourkela, Sri K.C. Sahoo from Balasore, Sri Suryanarayan Suri from Ranchi and Prof. K.N. Das from Gumla, Jharkhand discussed about various issues concerning the compensation package and all of them pointed out the fact that in most cases the people in the receiving end are betrayed and, even at time, hoodwinked by the money and muscle power.

THE THIRD TECHNICAL SESSION on "Cost concept: Viability of projects" was chaired

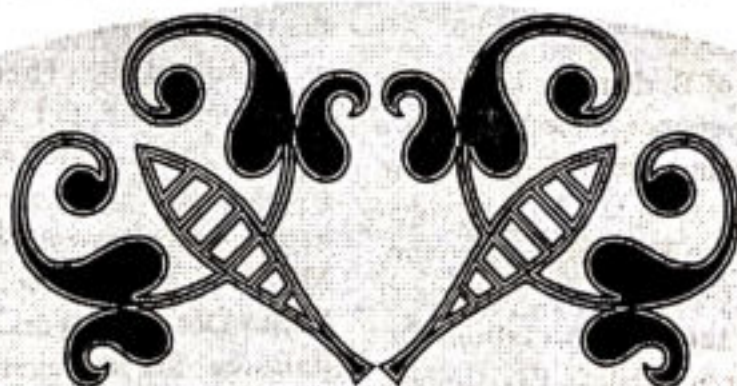
by Prof. P.K. Sahu, professor Berhampur University and Dr. Jagannath Dash, Professor and HOD, Anthropology, Utkal University presented the key-note address. Quoting from 'Indigenous Voice, Vol,1 No-11', he asserted : 'The water, the air, the sky belong to the people and who are you to snatch away such God's gifts from them? We should have, he said, the tears from our eyes and the pain in our heart to share the miseries of the people, affected by any mega-project. We should participate in their suffering. Narrating his own experience in the Rehabilitation-sites, he stated that the young and the old suffer the most on account of rehabilitation. The children in school often stand segregated. The funeral rites for the dead are denied, displaced are also not allowed perform their religious activities in the new settings. Therefore he sets the intricate question : which package will meet the said needs?

Therefore they should be rehabilitated thoroughly, as they were earlier. Social workers and activists must be given proper incentive and the forum to sort out the intricate issues and bring out the viable solution to the social issues.

The session met the inevitable end through a lively question-answer session involving tribal students, leaders and the delegates.

The third day of Programme started with the Inauguration of TRIBAL STUDENTS WORKSHOP at the same Hall. The inaugurator was Prof. Dr. Balagobinnda Baboo of Utkal University Sociology Deptt. and an authority on tribal displacement studies. The workshop involved the topic of ABVP achievement, ABVP & Tribal work, Tribal students Educational problems, Interaction with Tribal Commissioner and Research Programme, Local difficulties with authority regarding welfare schemes and projects and Valedictory.

With Best Compliments



M/s J. P. Enterprises

33/37, Dhangli Street, First Floor

Mumbai - 400 003

दिल्ली का प्रान्तीय अधिवेशन सम्पन्न भारत आतंकवादी शिविरों पर हमला बोले

"पाकिस्तान जेहाद के नाम पर आतंकवादियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत को पाक अधिकृत कश्मीर में चल रहे आतंकवादी शिविरों पर बिना देर किये हमला बोल देना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के दिल्ली के प्रान्तीय अधिवेशन में परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. कैलाश शर्मा ने यह विचार व्यक्त किये। अधिवेशन का आयोजन 11 जनवरी, 2002 को दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर के शंकरलाल हॉल में हुआ।

उद्घाटन भाषण में उन्होंने आतंकवाद पर चिन्ता व्यक्त करने के साथ-साथ वामपंथियों को भी फटकार लगाई। शिक्षा के भगवाकरण के मुद्दे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 'यह केवल छात्रों को बहकाने का कुत्सित प्रयास है। ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा अनेक विश्वविद्यालयों में पिछले अनेक वर्षों से दी जा रही है। अतः इसको भगवाकरण कहना मिथ्या प्रलाप है।' श्री शर्मा ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे छात्रों को इन वामपंथी हथकंडों के प्रति सचेत करें और शिक्षा जैसी संस्था की गरिमा और शुचिता को बरकरार रखें।

उद्घाटन के पश्चात् दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में शोभायात्रा निकाली गई। राष्ट्रभक्ति के नारों से गूँजती यह शोभायात्रा बाद में खुले अधिवेशन में बदल गई। खुले अधिवेशन का आरम्भ आतंकवाद के विरोध में हुए कवि सम्मेलन से हुआ। कवि सम्मेलन में श्री राजेश जैन 'चेतन' व श्री गजेन्द्र सोलंकी ने कविता पाठ किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ के उपाध्यक्ष नकुल भारद्वाज ने विश्वविद्यालय के बिगड़ते शैक्षिक माहौल पर असंतोष जताया तथा चेतावनी दी कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन समय रहते नहीं चेता, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जे.एन.यू. छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष श्री संदीप महापात्र ने वामपंथियों द्वारा प्रायोजित राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर कड़ा प्रहार किया।

छात्रों को संबोधित करते हुए परिषद् के राष्ट्रीय मंत्री श्री अतुल कोठारी ने कहा कि 'भारत में फैले आतंकवाद की जड़ वास्तव में पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान ही आतंकवाद को पोषण दे रहा है।' अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए श्री कोठारी ने कहा कि 'अपने

सुरक्षा तंत्र पर घमण्ड करने वाला अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को नहीं रोक पाया और एक ही हमले से उनके सब्र का बांध टूट गया। वही अमेरिका हमें शांति का पाठ पढ़ाना चाहता है। लेकिन अब हमें आतंकवादी शिविरों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए।'

खुले अधिवेशन के पश्चात् प्रस्ताव सत्र में प्रदेश सहमंत्री श्री त्रिलोक सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षिक दुरावस्था से संबंधित प्रस्ताव रखा। उन्होंने कुलपति को बिगड़ते शैक्षिक वातावरण एवं परिसर में बढ़ती राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया। प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश सहमंत्री सुश्री प्रगति बधवार तथा जे.एन.यू. इकाई अध्यक्ष श्री शिवशक्ति नाथ बख्शी ने किया। प्रस्ताव सर्व-सम्मति ने पारित हुआ।

समारोह सत्र में प्रांत संगठन मंत्री श्री चैतन्य प्रकाश ने छात्रों से राष्ट्र के प्रति समर्पण का आह्वान किया। अंत में ध्वजावतरण तथा वन्देमातरम् के साथ अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

परिषद् के प्रदेश मंत्री श्री जतिन मोहंती ने मंत्री प्रतिवेदन रखा तथा वर्ष भर के कार्यों का लेखा-जोखा अधिवेशन में प्रस्तुत किया, जो निम्नवत है :

आंदोलनात्मक कार्यक्रम

— 6 दिसम्बर को सभी महाविद्यालयों में बस पास काउन्टर खोलने एवं यू-स्पेशल बसों की संख्या बढ़ाने को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में रैली निकाली गयी व कुलपति को ज्ञापन दिया गया जिसमें 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

— जनवरी महीने में चीनी वस्तुओं की डम्पिंग के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया गया। चीनी सामानों की होली जलायी गयी, वाणिज्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव को ज्ञापन दिया गया। मुख्य वक्ता - श्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय मंत्री, कुल संख्या 212।

— 12 फरवरी को हटा द्वारा संभावित इड्डताल के मुद्दे पर अपना एक प्रतिनिधिमंडल हटा पदाधिकारी एवं कुलपति (दि.वि.वि.) से मिला।

— फरवरी माह में दि.वि.वि. के दीक्षान्त समारोह में विवादास्पद इतिहासकार रोमिला थापर को बुलाये जाने पर विरोध प्रदर्शन

गीता सार

● क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है, न मरती है।

● जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है। जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चात्ताप न करो। भविष्य की चिन्ता न करो। वर्तमान चल रहा है।

● तुम्हारा क्या गया, जो तुम रोते हो? तुम क्या लाये थे, जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था, जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो लिया इसी (भगवान) से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस, यही प्रसन्नता तुम्हारे दुःखों का कारण है।

● परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा-तेरा, छोटा-बड़ा, अपना-पराया, मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो।

● न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जायेगा। परन्तु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? तुम अपने आपको भगवान के अर्पित करो। यही सब से उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे हो जाता है, वह भय, चिन्ता, शोक से सर्वदा मुक्त है।

● जो कुछ भी तू करता है, उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन-मुक्त का आनन्द अनुभव करेगा।

शुभकामनाओं सहित

कौशल कुमार मिश्रा

एडवोकेट (दिल्ली हाईकोर्ट)

दूरभाष : 2046501 (चैम्बर), 2823569 (निवास), 9810524642 मोबाइल

किया गया। व्यापक प्रेस प्रसिद्धि मिली।

- अप्रैल माह में दि.वि.वि. के बी.कॉम (पास) के प्रश्नपत्र लीक होने पर परीक्षा नियंत्रक का घेराव किया गया।

- मई माह में बांग्लादेश राइफल द्वारा भारतीय जवानों के निर्ममतापूर्वक हत्या किए जाने पर बांग्लादेश उच्चायोग पर प्रदर्शन किया गया।

- 9 अगस्त को दि.वि.वि. (डी.यू.) में व्याप्त शैक्षणिक अराजकता, गुंडागर्दी व पेशेवर नेतागिरी के खिलाफ विशाल छात्र रैली का आयोजन किया गया जिसमें 1796 छात्रों ने भाग लिया।

- 1 अगस्त को जंतर-मंतर पर "कश्मीर में आतंकवाद" के खिलाफ प्रदर्शन किया गया।

रचनात्मक कार्यक्रम

- 6 दिसंबर को अंबेडकर पुण्यतिथि पर तीन स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुये।

- जनवरी में उत्तरी परिसर एवं दक्षिणी परिसर (दि.वि.वि.) में क्रमशः तीन दिवसीय एवं द्विदिवसीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। उत्तरी परिसर में मेले का उद्घाटन प्रख्यात असमिया लेखिका इंदिरा गोस्वामी तथा दक्षिणी परिसर में आयोजित पुस्तक मेला का उद्घाटन प्रख्यात पत्रकार सूर्यकांत वाली ने किया।

- सुभाष जयंती पर जनकपुरी विभाग में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुल संख्या 96 रही।

- गुजरात भूकंप आपदा में अपने से बिछुड़े लोगों के लिये सात महाविद्यालयों में श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम आयोजित किये गये। राहत कार्य हेतु 25,000 रुपये भेजे गये।

- मार्च महीने में विश्व युवक केन्द्र सभागार में नये-पुराने कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 'गणतंत्र का अर्द्धशतक' विषय पर परिसंवाद का आयोजन किया गया। वक्ता - श्री बाल आष्टे, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभाविप, श्री गोविंदाचार्य, पूर्व क्षेत्रीय संगठन मंत्री, अभाविप एवं श्री अरुण जेटली, केन्द्रीय विधि मंत्री रहे।

- जे.एन.यू. में "वैश्वीकरण एवं समाज में उसका प्रभाव" विषय पर श्री गोविंदाचार्य, पूर्व महासचिव भाजपा का व्याख्यान आयोजित हुआ। कुल संख्या 350 रही।

- जे.एन.यू. में अम्बेडकर जयंती पर "अम्बेडकर की प्रासंगिकता"

विषय पर भाषण आयोजित किया गया। वक्ता - श्री संजय पासवान (सांसद), एवं श्री राजकुमार फुलवारिया (पूर्व प्रदेश सह-संगठन मंत्री रहे)। कुल संख्या 70 रही।

अन्तराज्य छात्र जीवन दर्शन (SEIL)

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों, सिक्किम एवं अंडमान से आए 38 प्रतिनिधियों का सार्वजनिक अभिनंदन समारोह जे.एन.यू. सिटी सेंटर में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि - दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री शांति देसाई रहे। प्रतिनिधियों का दिल्ली-भ्रमण एवं प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं केन्द्रीय खेल मंत्री सुश्री उमा भारती से मिलन का कार्यक्रम रहा।

विकासार्थ विद्यार्थी (SF D)

- 15 सितम्बर को "इंजीनियर्स डे" पर दि.वि.वि. के टैगोर हॉल में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आई.आई.टी. मद्रास से प्रो. वी.एस.राजू, RITNAND BALVED EDUCATION FOUNDATION के FOUNDER PRESIDENT डा. अशोक चौहान, पुंज लॉयड कम्पनी के कार्यकारी निदेशक श्री सुभाष जगोटा आदि ने अपने विचार रखे। कुल 160 छात्रों ने भाग लिया।

प्रतिनिधित्वात्मक कार्यक्रम

- 4 दिसम्बर को साऊथ कैम्पस में छात्र नेता अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। कुल संख्या 32 (छात्रा 7)।

- दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) में उपाध्यक्ष पद पर अपनी जीत हुई है। साथ ही 5 कार्यकारी पार्षद भी विजयी हुये।

- जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (JNUSU) चुनाव में अपने 10 पार्षद विजयी हुये हैं।

प्रवेश सूचना केन्द्र

- जे.एन.यू. में 15 दिन तक "असिस्टेंस बूथ" लगाया गया।

- 20 जून 2001 तक 27 स्थानों पर प्रवेश सूचना केन्द्र लगाये गये। जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत की Website: www.abypdelhi.org पर भी विद्यार्थियों को जानकारी उपलब्ध करायी गयी। चल सूचना केन्द्र भी चलाये गये। दो केन्द्रों पर कम्प्यूटर से भी जानकारी दी गयी।

क्रैश कोर्स

- कैम्पस विभाग द्वारा एल.एल.बी. प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए "क्रैश-कोर्स" का आयोजन किया गया।

इसमें कुल 145 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विदित हो कि कैम्पस विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों से एल.एल.बी. क्लेश कोर्स का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इस बार के क्लेश कोर्स की यह विशेषता रही कि अध्यापन अपने परिषद् कार्यकर्ताओं द्वारा ही किया गया।

9 जुलाई विद्यार्थी दिवस

- कैम्पस, धोला कुआं, कालकाजी तथा नई दिल्ली विभाग में कार्यक्रम हुए जिनमें कुल 350 विद्यार्थी सहभागी हुए।

नवागंतुक छात्र अभिनन्दन

- 8 महाविद्यालयों में नवागंतुक छात्र-अभिनन्दन किया गया।

छात्रा कार्य

- 9 मार्च महिला दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था "भारतीय चिन्तन में नारी" इसमें मुख्यवक्ता श्रीमती सरस्वती बाली (उप-प्राचार्य कालिन्दी कॉलेज) एवं श्रीमती रमा पाण्डे (पीडियाकर्मी) मुख्य अतिथि रही। कुल संख्या 70 रही। (35 छात्राएं)
- इस वर्ष का छात्रा प्रदेश वर्ग 19, 20 अक्टूबर को पूर्वी विभाग में सम्पन्न हुआ। कुल संख्या 25 रही।

पृष्ठ 9 का शेष-

स्वतंत्र भारत में भारतीय विधाओं यथा शास्त्रीय संगीत, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष, कला, साहित्य, नाटक, शिल्प, नृत्य, गोवंश, नदी समृद्धि, कृषि पद्धति आदि के विनाश के सुनियोजित प्रयत्न किए गए हैं। संस्कृत को पाठ्यक्रमों से हटाकर मृत बनाने के अनेक प्रयत्न किए गए। भारतीय वास्तु-शास्त्र को दकियानूसी और कालातीत कह कर उपेक्षा के गर्त में धकेला गया। भारतीय खेलों को तो लगभग बहिष्कृत कर ही दिया गया है। इनकी सुधि लेने वाला तो अब भारत भूमि में सरकारी स्तर पर कोई नहीं है। ये भी तो शिक्षा के अंग हैं। स्कूलों में इनके सुनियोजित प्रोत्साहन और इनकी विशेषताओं के उल्लेख से शिक्षा में भारतीयता का समावेश होगा। इसलिए इन्हें भी पाठ्यक्रमों का अंग बनाना पड़ेगा।

समय हमें पीछे छोड़ रहा है। हम उस क्षति की पूर्ति कैसे करेंगे जो हो गई है?

चलिए, आज से ही सही, शिक्षा का भारतीयकरण प्रारंभ हो।

With Best Compliments From :



Ashok Sahdev

NATIONAL REFRIGERATION COMPANY

बीता वर्ष : एक दृष्टिक्षेप

वर्ष 2001, नई सहस्राब्दी के रूप में जिसका दिल्ली और देश के युवा विद्यार्थियों ने धूम-धाम से स्वागत किया था, ने पूरे वर्ष भर जहाँ शिक्षा जगत की व्यवस्थाओं एवं व्यक्तियों पर प्रश्नचिह्न खड़े करने का काम किया वहीं जाते-जाते एक ऐसी गहरी चोट देकर गया है जिसे भरना आसान नहीं है।

दिल्ली के शिक्षा जगत को तो यह वर्ष शायद आइना दिखाने के लिये ही आया था। जिस विश्वविद्यालय में जे.पी. की एक अपील ने क्रांति का सूत्रपात किया था, देखते-ही-देखते वहाँ देशद्रोह और लोकतंत्र की हत्या की साजिशें पनपने लगीं। और यह सब ऐसी खामोशी के साथ हुआ कि मस्ती में झूमता छात्रवर्ग अपने ही बीच में छिपे दरिन्दों को भी न पहचान सका। यह भी साबित हुआ कि एक खास विचारधारा के लिये उसकी अपनी विचारधारा बड़ा है और देश की संप्रभुता छोटी।

वर्ष का प्रारंभ हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परम्परा के अनुसार महामहिम राष्ट्रपति अथवा मुख्य न्यायाधीश स्तर के किसी व्यक्ति के स्थान पर विवादास्पद वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर को आमंत्रित किया गया। कुछ विद्यार्थियों तथा संगठनों ने इसका विरोध करना चाहा और कुलपति की मौन स्वीकृति से पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठियाँ भांजी। कुछ शिक्षक संगठनों ने भी इसका विरोध किया।

धुरवामपंथी छात्र संगठन पी.एस.यू. ने वि.वि. परिसर में गोष्ठी का आयोजन किया जिसमें जे.के.एल.एफ. नेता यासीन मलिक को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। संसद भवन पर हुए हमले की साजिश में पकड़े गये जाकिर हुसैन कॉलेज के प्राध्यापक जिलानी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे।

छात्र संगठन के नाम पर देश द्रोही व असामाजिक गतिविधियों में संलग्न स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया की गतिविधियाँ इतनी बढ़ गई कि सरकार को उस पर प्रतिबंध तक लगाना पड़ा। भारत के विश्वविद्यालयों में आतंकवाद के समर्थन की जमीन तैयार करने का काम कितना जड़ पकड़ चुका है, यह सिमी की गतिविधियों से

साबित हुआ।

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव सितंबर माह में हुआ जिसमें पेशेवर छात्र राजनीति का जीता-जागता उदाहरण मिला स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में, जहाँ एक ही कॉलेज से छात्र संघ के चुनाव के लिए 77 प्रत्याशी थे। छात्र संघ में सचिव पद पर विजयी प्रत्याशी विकास शौकीन को एक महीने के भीतर ही अपने पद से हटना पड़ा जब उसके द्वारा फर्जी अंक तालिका पर एक साथ दो कोर्सों में प्रवेश का भंडा फोड़ हुआ।

विश्व विद्यालय की वार्षिक परीक्षाओं में बी.कॉम. पास का प्रश्न पत्र लीक होने की घटना ने विश्वविद्यालय की समूची परीक्षा प्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगा दिया। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर पड़ा परदा भी हट गया।

एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रमों में, विशेषतः इतिहास की पुस्तकों में होने वाले बदलाव के विरोध में शुरू हुआ अभियान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। त्रुटि पूर्ण तथ्यों के आधार पर इतिहास की पुस्तकों में जोड़े गये अंशों को संशोधित करने के सरकारी प्रयास पर मतभेद प्रस्तुत करने के लिये अकादमिक बहस कम, धरने, प्रदर्शन एवं जलूसों का आयोजन अधिक हो रहा है।

संस्कृत, ज्योतिष एवं वैदिक गणित के नये पाठ्यक्रम शुरू करने को शिक्षा के धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर हमला बताया जा रहा है। जिन विषयों को कॉलेज तथा विश्वविद्यालय पढ़ाना चाहते हैं, विद्यार्थी स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं, उनके पठन-पाठन पर भी बुद्धिजीवी एतराज कर रहें और उसके खिलाफ एक अंधी बहस छेड़े हुए हैं।

मानवीय संवेदनाओं की पैरोकारी करने वाले छात्र एवं शिक्षक अफगानिस्तान पर हमले के विरोध में पच्चे बांटते हैं, प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सैद्धिग्य गतिविधियों में लिप्त एक विदेशी छात्र जब छात्रावास में तुलसी के चित्र पर अपना जूता रखता है एवं अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। यही छात्र जब छात्रावास से निकाल दिया जाता है तो कुलपति की पहल पर उसे शिक्षकों के लिये बने ट्रांजिट हॉस्टल में आवास उपलब्ध कराया जाता है।

जिन कुलपति महोदय से छोटे-मोटे विषयों को लिये भी न केवल सामान्य छात्र अपितु छात्रों, कर्मचारियों तथा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को भी मिलने के लिये पूर्वानुमति लेनी होती है, तलाशी देकर ही उस लोहे के पिंजड़े में घुस सकते हैं, जिसमें कुलपति कार्यालय है, वही संसद भवन पर हुए हमले में आरोपी जिलानी की न केवल सीधी पहुँच थी बल्कि नियमित आना-जाना भी था।

13 दिसंबर को संसद पर हुआ हमला जहाँ देश के लोकतंत्र एवं संप्रभुता के लिये चुनौती था वहीं दिल्ली के शिक्षा जगत के चेहरे पर कालिख पोत गया। लश्करे तैयबा और जैशे मुहम्मद के आतंकवादी उन पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क सूत्र दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों से जुड़े हुए थे।

निरंकुशता की हद उस समय हो गई जब इतने संगीन अपराध में गिरफ्तार किये गये जिलानी के समर्थन में एकवर्ग न सिर्फ सामने आया बल्कि उसकी मदद के लिये सार्वजनिक चन्दा करने का दुस्साहस भी किया। भुर वामपंथ की आड़ में देश विघातक गतिविधियों में लिप्त यह लोग अपनी गतिविधियाँ चोरी-छिपे नहीं बल्कि डंके

की शोट पर कर रहे हैं और मानवाधिकार तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य को नारे लगाकर देश को विश्वविद्यालयों को आतंकवाद के अड्डों में बदलने की साजिश जारी है।

चाहे वह दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति अथवा मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर एक विवादास्पद व्यक्ति को बुलाये जाने का मामला हो, यासीन मलिक को परिसर में बुलाने की घटना हो, सिमी पर प्रतिबंध का विरोध हो, इतिहास पुस्तकों में बदलाव का विरोध हो, जे.एन.यू. में सेनाधिकारी पर हमले का मामला हो अथवा संसद पर हमले की साजिश में शामिल आरोपी का समर्थन और उसके लिये चंदा करने का दुस्साहस, हर घटना में दोषियों एवं राष्ट्रद्रोहियों के समर्थन में यही निश्चित चेहरे हैं जो सामने आते हैं। यही निश्चित विचारधारा है जो उनके साथ खड़ी होती है।

वर्ष 2001 ने स्पष्ट संकेत दिये हैं कि शिक्षा क्षेत्र को अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये अपने अंदर पनप रहे विदेशी षड्यंत्रों को बेनकाब करने एवं देश विरोधी उन्माद पैदा करने वाले तत्वों को पहचानने एवं उनकी जड़ों पर हमला करने की जरूरत है।

With Best Compliments From :



Shiv Mishthan Bhandar

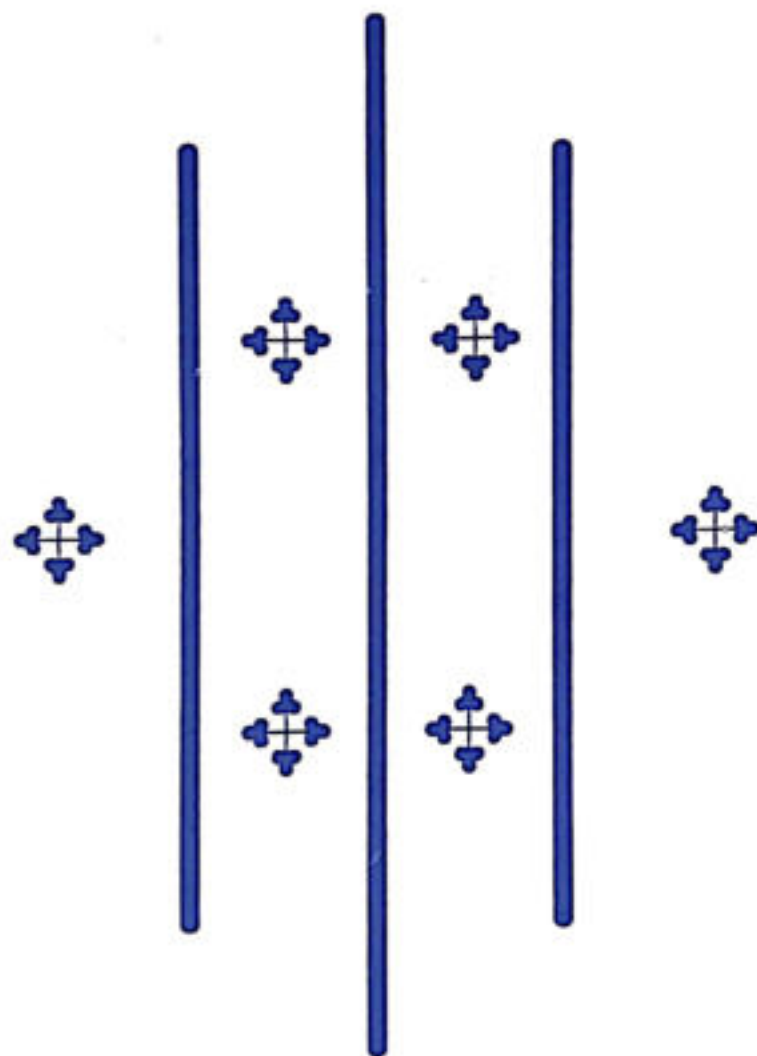
1896, Hanuman Mandir, Jamuna Bazar, Delhi - 110 006

Tel. : 3867951, 3861513



शैक्षिक माँगों के समर्थन में आयोजित विशाल छात्र रैली

With Best Compliments



Pankaj Kumar Jain

M/S PANKAJ CONTRACTOR & ENGINEERS

(GOVT. CONTRACTOR AND SUPPLIERS)

4300/E, SINGHAL BHAWAN,

3, ANSARI ROAD, DARYAGANJ, NEW DELHI - 110002

With Best Compliments From :

Civil Services
CHRONICLE
• AWARENESS • AMBITION • SUCCESS

*India's
Premier
Career
Magazine*

CHRONICLE PUBLICATIONS (P) LTD.

C-6/52, SDA, New Delhi-110016. Ph. : Off. 6519761, 6532691
Fax : 6526443 e-mail : chronicle@nda.vsnl.net.in

With Best Compliments



La Belle Cosmetics (India)

P. O. Box No. 11528, New Delhi - 110046

Ph. : 5500411, 5507596, Resi. : 5532065

Telefax : 5611623

JNUSU Elections 2001

Analysis of ABVP's Performance

In the JNUSU Election 2001-02 held on 12th October 2001, all the four Cental Panel posts were won by the AISF-SFI candidates with substantial leads over the ABVP candidates, majority of the councilors from the non science schools were also won by the AISF-SFI alliance. Apart from this electoral result however, there are some other interesting aspects of this election from the point of view of the Vidyarthi Parishad, which also cast light on the reasons behind the sweep by the AISF-SFI.

Let us firstly look at the votes secured by the four organisations in the fray for all the four posts. For the presidents post the SFI candidate Albeena Shakil secured 1606 votes. ABVP candidate Sandeep Mahapatra secured 1017, while AISA and NSUI got 235 and 110 vote respectively. For the Vice-President, post the AISF candidate Rohit got 1564 votes while the ABVP candidate Anshu Joshi got 933 votes, AISA and NSUI got 212 and 226 votes respectively. For the post of the General Secretary, the AISF candidate Ginu +karia Oomen got 1311 votes, the ABVP candiate Shiv Shakti Nath Bakshi got 995 votes, AISA and NSUI got 443 and 236 votes respectively. For Joint-Secretary, SFI candidate Parimal Maya Sudhakar got 1363, ABVP candidate Leeladhara M. Bhandary got 893 votes while AISF and NSUI got 222 and 432 respectively.

Thus, the AISF-SFI tally for the four posts from President to Joint Secretary respectively were 1606, 1564, 1311 and 1353, This is a signficnt Jump over AISF-SFTs last year's tally of 955, 1094, 1130 and 889 votes respectively. While the highest vote secured by their candidate in 2000 was 1130, this this year their lowest level is 1311. This shows that the SFI-AISF vote have increased in all the four posts in the range of 200 to 500 votes. This is the first significant point to be noted in this years elections.

Similarly, the votes secured by the ABVP in the four posts respectively are 1017, 933, 995 and 893 votes respectively while last year's lowest level for ABVP was 827, this year, it is 893. Again, last year's highest level for ABVP was 956, this year it is 1017.

This shows that the votes secured by ABVP's Central Panel candidates have increased in the range of 60 to 70 votes. This is the second significant point in this year's elections, that ABVP's votes have increased even though the increase in much less than the AISF-SFI's increase.

This makes it clear that the dramatic increase in votes secured by AISF-SFI has not been at the expense of ABVP, in the sense that there has been no corresponding decrease in ABVP's level. Thus, the question then is, from whom these votes metamorphosed into AISF-SFI votes?

To answer this question, let us compare AISA and NSUI's tally in the current year to that of the last year. AISA's tally this year is 235, 212, 443 and 222 votes respectively while NSUI's is 110, 226, 236 and 432 respectively. If we add up the tally of these two organisations for each post, it comes to 445, 438, 679 and 654 votes respectively. As regarding last year's results, AISA's for the 4 posts were 690, 558, 594 and 402 votes respectively, while NSUI's tally was 357, 530, 308 and 759 respectively, Adding the

votes of the 2 organisations for each post as we had done for the current year, we have a AISA+NSUI tally 1047, 1088, 902 and 1161 votes respectively. Thus, AISA+NSUI's highest tally last year was 1161 while this year it is 679. Again, these 2 organisation's combined lowest tally last year was 902 while this year it is 438. Therefore, AISA+ NSUI's combined votes have decreased this year by at least 500 votes for all the posts compared to last year's votes.

This provides us with the answer to the question earlier raised, i.e., from where AISF-SFI votes increased by almost 500 in the current year. It is thus, aparent that while there has been no shift from ABVP to AISF-SFI, as ABVP votes increased this year in the range of 60-70 votes, there has been a massive corresponding shift from AISA and NSUI to AISF-SFI, which resulted in AISF-SFI sweeping all the four ports by substantial margins and organisation like AISA which were already marginal, getting wiped out almost

completely. What are the probable reasons for this shift?

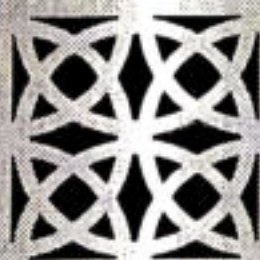
As ABVP has steadily established itself as a major force on the campus and has also steadily improved on its electoral tally almost every year since 1995, students politics on JUN campus has increasingly begun to revolve around the ABVP with almost a complete polarisation of the campus in to pro-ABVP and anti-ABVP forces. The opposition to ABVP too, is not based solely on ideological grounds but is increasingly coming to be organised on the bases of religion, caste, region ect.. Most of these forces are opposed to ABVP due to scuh factors and not due to ideological commitment to any ideology. Their purpose is to defeat ABVP and thus to vote for any political formation which they perceive as being able to oppose ABVP effectively.

This anti-ABVP vote used to be divide in to three unequal chunks, with SFI-AISF getting the major share and AISA and NSUI getting minor shares. But last years "shock victory" of the ABVP's Presidential candidate by one vote gave a sharp jolt to the anti-

ABVP voters who this time felt that consolidating behind AISF-SFI was the best bet in order to defeat ABVP Politically. Some recent attempts by the SFI-AISF to mobilise voters on communal lines by creating a controversy about the recent presidential candidate about his stand regarding "Hindu Rashtra" during the presidential debate also created a polarisation among certain sections against ABVP and therefore in favour of SFI-AISF.

These are the reasons for the consolidation of anti-ABVP votes solidly behind the AISF-SFI leading to the vote share of this alliance increasing by 500 votes, and electoral defeat of the ABVP inspite of an increase in the latter's votes. Therefore, what can be predicted for the coming few years at least is further polarisation between the AISF-SFI and ABVP, the only two students organisations left in the field and the further marginalisation of the smaller organisations like AISA and NSUI. ABVP will have to take this as a challenge and will have to be prepared to contest elections in the completely bipolar system in the coming days.

शुभकामनाओं सहित



श्री कृष्ण अग्रवाल

बी.एम.- 3, शालीमार बाग, दिल्ली

भारत तथा नेपाल समान संस्कृति के वाहक : दत्तात्रेय

भारत तथा नेपाल के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों का एक लम्बा इतिहास रहा है। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्र विरोधी ताकतों दोनों देशों के बीच कड़वाहट घोलने में जुटी हुई हैं। माओवादी उग्रवादियों, आई.एस.आई. तथा ईसाई मिशनरियों द्वारा रचे जा रहे कूचक्र के कारण न केवल नेपाल बल्कि नेपाल सीमा से सटे हुए उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी राष्ट्र विरोधी स्वर मुखर होता जा रहा है।

सीमान्त क्षेत्रों में पनप रहे इस षड्यंत्र से घिंति होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती रही है। हाल के दिनों में माओवादियों द्वारा चलाये जा रहे भारत-विरोधी अभियान को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् उत्तरांचल प्रदेश ने 'नेपाली छात्र सम्मेलन' तथा राष्ट्रीय सुरक्षा जन जागरण पद यात्रा का आयोजन किया। दोनों ही कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिये युवा शक्ति को जागृत एवं संगठित करना था।

नेपाली छात्र सम्मेलन—नेपाली युवाओं के मध्य उग्रपन्थी माओवादी विचारधारा के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिये गत 26 नवम्बर, 2001 को ऋषिकेश (देहरादून) में प्रथम 'नेपाली छात्र सम्मेलन' आयोजित किया गया। सम्मेलन के माध्यम से नेपाली विद्यार्थियों को माओवादियों का वास्तविक चेहरा दिखाने तथा उनके मध्य पनप रही भारत-विरोधी भावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया।

सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए परिषद् के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि 'भारत तथा नेपाल के बीच आरम्भ से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं, जो मात्र व्यापार तक ही सीमित नहीं हैं। वास्तव में दोनों ही राष्ट्र हिन्दू संस्कृति के वाहक हैं तथा दोनों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकरूपता है।' उन्होंने कहा कि 'नेपाल के गृह मंत्रालय के अनुसार भारतीय सीमान्त क्षेत्र में इस समय लगभग 25 हजार माओवादी विद्रोही सक्रिय हैं, जो दोनों देशों की सुरक्षा, समृद्धि तथा विकास के लिये खतरा बने हुए हैं। इनको समाप्त करके ही भारत एवं नेपाल शक्तिशाली बन सकते हैं।' श्री दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों का

आह्वान किया कि वे भारत के साथ मिलकर हिन्दू संस्कृति का सम्पूर्ण विश्व में प्रसार करें।

सम्मेलन में भाग लेने आये 200 से भी अधिक नेपाली छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों ने विघटनकारी ताकतों को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया। भारत में पढ़ रहे नेपाली छात्रों की समस्याओं से प्रदेश सरकार को अवगत कराने के लिये 3 नेपाली विद्यार्थियों एवं दो परिषद् कार्यकर्ताओं की एक समिति का भी गठन किया गया। सम्मेलन का समापन उत्तरांचल के मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी ने किया।

राष्ट्रीय सुरक्षा जन जागरण पदयात्रा—सीमान्त क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं को जानने तथा सरकार को उनसे अवगत कराने के लिये उत्तरांचल प्रदेश के परिषद् कार्यकर्ताओं ने 22 दिवसीय पदयात्रा का आयोजन किया। यात्रा का शुभारम्भ पिथौरागढ़ के पौराणिक शिवालिक मन्दिर से हुआ। मन्दिर में पूजा-अर्चना के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त कार्यवाह ने वन्देमातरम् के उद्घोष के बीच झण्डी दिखाकर पदयात्रियों को रवाना किया।

यात्रा के आरम्भ में पदयात्री पिथौरागढ़ से 150 कि. मी. तक बस से गये। इसके पश्चात् घटिया बगड़ से टनकपुर तक 503 कि.मी. तक की यात्रा पैदल चलते हुए 21 दिनों में पूरी की गई। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता 18 हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित भारतीय गौव आदि कैलाश तक गये तथा गौववासियों से मिलकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। कार्यकर्ताओं ने 286 गौवों में स्थित कुल 154 कॉलेज तथा स्कूलों में सम्पर्क किया। भारत-नेपाल मैत्री सम्बन्धों को प्रगाढ़ करने के लिये आयोजित की गई इस पदयात्रा में निम्न 4 बिन्दुओं पर कार्य किया गया।

—सीमावर्ती क्षेत्र की आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं की जानकारी प्राप्त करके उनके निराकरण का प्रयास करना।

—आई.एस.आई. तथा माओवादी गतिविधियों के कारण भारत-नेपाल मित्रता एवं प्रगति पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को सचेत करना।

—भारत तथा नेपाल की सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करना।

—नेपाली नागरिकों को बताना कि वे भारत में विदेशी नहीं हैं।

यात्रा के दौरान क्षेत्रीय जनता की कई समस्याएँ उभरकर सामने आईं। लगभग 12 हजार फीट की ऊँचाई पर बसा 'कुटी' गीब आजादी के 54 वर्ष बाद भी विकास की किरण से अछूता है। इस सीमान्त गीब के निवासियों को मोटर मार्ग तक पहुँचने के लिये आज भी 103 कि. मी. पैदल चलना पड़ता है। चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से ये लोग आज भी वंचित हैं। कार्यकर्ताओं ने यह महसूस किया कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिये प्रदेश सरकार को सीमान्त क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था भी लचर है और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि स्थानीय पुलिस और कस्टम विभाग के कर्मचारी इनको बेवजह परेशान करते हैं। इसके अतिरिक्त 'इनर लाइन परमिट' भी हमारी आन्तरिक सुरक्षा के लिये एक खतरा बन गया है। 'इनर लाइन परमिट' की व्यवस्था पहले सीमान्त क्षेत्र जौल जीवी से लागू होती थी। किन्तु अब इसको 200 किमी. अन्दर स्थित दयालेक से लागू किया जाता है। इस कारण सीमा के भीतर 200 कि.मी. तक का

क्षेत्र सन्दिग्ध गतिविधियों का केन्द्र बन गया है। क्षेत्रवासियों को मानना है कि भारत की सुरक्षा के लिये यह परमिट पुनः जौलजीवी से लागू किया जाना चाहिए। सीमान्त क्षेत्र की एक बड़ी समस्या तस्करी है। इससे न केवल अपराध बढ़ रहे हैं, बल्कि व्यापार को भी नुकसान हो रहा है। भारत सरकार को तस्करी रोककर इस क्षेत्र को व्यापारिक केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहिए।

भारत-नेपाल सीमान्त क्षेत्र के अन्तिम गीब कुटी, कालापानी तथा आदिकैलाश तक की पदयात्रा का समापन 10 नवम्बर, 2001 को टनकपुर (धम्पावत) में आयोजित एक भव्य समारोह में हुआ। समापन समारोह में उत्तरांचल सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहन सिंह रावत ने सैकड़ों विद्यार्थियों तथा आम जनता के साथ पदयात्रियों का स्वागत किया। समापन समारोह में परिषद् के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री नागेन्द्र नाथ तथा उत्तरांचल प्रान्त के अध्यक्ष डॉ. दिनेश जोशी भी उपस्थित थे। पदयात्रा के संयोजक पिथौरागढ़ के विभाग प्रमुख श्री वसन्त वर्मा थे, जबकि व्यवस्था प्रमुख का दायित्व पिथौरागढ़ के जिला संगठन मंत्री कपिल सामंत एवं जिला प्रमुख गोपू मेहर ने निभाया।

उत्तरांचल राज्य छात्रसंघ चुनावों में परिषद् को भारी सफलता

नवगठित उत्तरांचल राज्य में हुए प्रदेश छात्र संघ चुनावों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने भारी जीत हासिल की।

परिषद् को सबसे बड़ी जीत गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में मिली, जहाँ छात्र संघ अध्यक्ष पद पर परिषद् ने अपना परचम फहराया। इसके अतिरिक्त रुड़की (आई.आई.टी.) तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर भी विद्यार्थी परिषद् बहुमत के साथ जीतकर आई।

विभिन्न राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हुए विद्यार्थी परिषद् ने कॉलेज छात्र संघ चुनावों में भी अपने वर्चस्व का प्रदर्शन किया। इस वर्ष उत्तरांचल प्रदेश में कुल चालीस डिग्री कॉलेजों में चुनाव हुए। परिषद् ने इनमें से 19 कॉलेजों में अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। इनमें मंसूरी, देवप्रयाग, चम्बा, कर्णप्रयाग, पिथौरागढ़, जोशीमठ आदि कॉलेज प्रमुख हैं। दूसरी ओर 27 कॉलेजों परिषद् के प्रत्याशी महामंत्री पद के लिये निर्वाचित हुए। जिन कॉलेजों में परिषद् प्रत्याशियों ने महामंत्री पद हासिल किया है, उनमें अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, रामनगर, मंसूरी, ऋषिकेश आदि प्रमुख हैं।

परिषद् का विजय रथ इतने पर ही नहीं थमा। एफ.आर.आई. देहरादून के डीम्ड विश्वविद्यालय में हुए छात्रसंघ चुनावों में भी परिषद् ने ही जीत हासिल की।

चुनावों में प्रमुख बात यह रही कि जहाँ परिषद् ने आधी से अधिक सीटें जीतीं, वहीं दूसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी रहे। एन.एस.यू.आई. तथा वामपंथी छात्र संगठन बमुश्किल अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। महामंत्री पद के लिये जहाँ परिषद् ने 27 सीटें जीतीं, वहीं आइसा मात्र एक सीट हासिल कर सकी। शेष सभी सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में गईं।

संसद पर हमले से उपजा आक्रोश

नई दिल्ली। समाचार माध्यमों द्वारा संसद पर हमले की जानकारी प्राप्त होते ही पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। शुभ छात्र-युवाओं ने स्थान-स्थान पर जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं, रैली, जुलूस, पुतला दहन आदि माध्यमों से अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया।

प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ताओं ने घटना के चार घंटे के अंदर ही 75 से अधिक स्थानों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। पूरे देश में अभी तक भी इस प्रकार के आयोजनों का अनवरत क्रम जारी है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्, बरेली के कार्यकर्ताओं ने संसद भवन पर आतंकवादी हमले के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर संसद पर घटी आतंकवादी घटना की जानकारी मिलने पर परिषद् के कार्यकर्ताओं ने बरेली कॉलेज में एक बैठक की तथा विरोध प्रकट करते हुए आतंकवाद का पुतला फूँका और कॉलेज बंद करवाया।

विद्यार्थी परिषद् के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बरेली कॉलेज में धुमे तथा प्राचार्य महोदय से विचार विमर्श करने के पश्चात् कॉलेज बंद करवाया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं व छात्रों को सम्बोधित करते हुए परिषद् के प्रांतीय कार्यसमिति के सदस्य रणवीर सिंह यादव ने कहा कि संसद भवन में घटी आतंकवादी घटना भारतीय इतिहास की एक काली घटना है, इससे यह सिद्ध होता है कि आतंकवादियों के हौंसले किस तरह बुलन्द है। उन्होंने कहा आज आतंकवाद के विरुद्ध सीधी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है।

विद्यार्थी परिषद् के महानगर मंत्री नितेश सिंह तौमर ने कहा कि समय आ गया है जब समस्त भारतीयों को आतंकवाद के खात्मे के लिये संघर्ष हेतु कमर कसनी होगी। आतंकवादियों को यह संदेश देना जरूरी है कि यदि वे हमारे देश को नष्ट करने के लिये अपनी जान हथेली पर रख सकते हैं तो हम भारतीय भी अपने देश की रक्षा हेतु जान की बाजी लगा सकते हैं।

कॉलेज प्रमुख प्रवीन गंगवार ने कहा कि विद्यार्थी परिषद् मांग करती है कि आतंकवादियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाये ताकि भविष्य में इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को सबक मिले। इसके पश्चात् कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों का पुतला फूँका और जमकर नारेबाजी की तथा आतंकवादियों से भिड़ते हुए प्राण न्योछावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों की आत्मा की शांति के लिये एक मिनट का मौन रखा गया।

विद्यार्थी परिषद् कार्यकर्ताओं ने कुतुबखाना चौराहे पर

आतंकवाद का पुतला फूँका और जमकर नारे लगाये। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है और इसकी की राह पर भारत में आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं।

विद्यार्थी परिषद् की आगरा इकाई ने संसद पर आतंकी हमले के षड्यंत्रकारी जिलानी के खिलाफ ठोस कार्यवाही की मांग को लेकर शवयात्रा के कार्यक्रम का आयोजन किया।

जिलानी के पुतले के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पाक विरोधी नारे लगाते हुए सूरजमल जाट इण्टर कॉलेज पहुँचे जहाँ शिक्षकों एवं छात्रों का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् यह शवयात्रा सेंट जांस कॉलेज पहुँची जहाँ विज्ञान एवं कला, दोनों ही संकायों के छात्रों तथा शिक्षकों ने समर्थन दिया तथा बड़ी संख्या में छात्र शवयात्रा रूपी जुलूस के साथ हो लिये।

छात्र हाथों में नारे लिखी तख्तियाँ लेकर देश भक्ति के नारे लगा रहे थे। आगरा कॉलेज में पहुँचकर यह जुलूस धूम-धूमकर छात्रों में अपना संदेश फैला रहा था तथा शिक्षकों व छात्रों से समर्थन माँग रहा था। इसी बीच कॉलेज प्रशासन के कुछ लोगों ने कुछ उपद्रवी तत्वों को साथ लेकर कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया। वातावरण बिगड़ते देख परिषद् कार्यकर्ताओं ने तुरंत कार्यक्रम स्थगित किया एवं कॉलेज से बाहर आ गये। किंतु वहाँ मौजूद कुछ अराजक तत्वों द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये जाने के बाद हालात बेकाबू हो गये और इसकी परिस्थिति पथराव के रूप में हुई जिसमें अनेक छात्र व शिक्षक घायल हुए।

घटना के पश्चात् कॉलेज की प्राचार्य डॉ. राजकुमारी शर्मा के बयान ने आग में घी का काम किया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के साथ स्कूली बच्चे थे तथा वे कॉलेज में गुंडागर्दी कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वे कॉलेज में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगी तथा भविष्य में कोई भी जुलूस कॉलेज में आया तो सबक सिखाया जायेगा।

इस घटना एवं कॉलेज प्रशासन के व्यवहार को लेकर छात्रों तथा नागरिकों में जबरदस्त तीखी प्रतिक्रिया हुई तथा कॉलेज प्राचार्या की कुत्सित मानसिकता की आलोचना विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा की गई।

दूसरी ओर अभावपि कार्यकर्ताओं ने अगले दिन पुनः आगरा कॉलेज के गेट पर जनसभा की एवं गद्दार जिलानी का पुतला फूँका। वक्ताओं ने कॉलेज प्रशासन पर पाक समर्थन नारे लगाने वालों को संरक्षण देने के लिये लताड़ा तथा भारत विरोधी मानसिकता नहीं बदलने पर गम्भीर परिणाम की चेतावनी दी।

महिलायें संगठित होकर अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलन्द करें : गीता ताई

आगरा। महिलाओं को संगठित होकर अन्याय एवं अत्याचारों के विरुद्ध आवाज बुलन्द करनी चाहिए। भोगवादी मानसिकता का घोर विरोध करना समय की आवश्यकता है। आज देश को ही नहीं बल्कि विश्व को बदलने का स्वप्न देखने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उक्त विचार अभिविप की छात्रा प्रमुख गीता ताई ने परिषद् की प्रान्तीय छात्रा सम्मेलन को स्थानीय सुभाष पार्क स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में व्यक्त करते हुए कहा कि कितनी ही महिलाओं को निर्वस्व किया जाता है। सुन्दरी प्रतियोगिता के माध्यम से नारी को उपभोग की वस्तु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इतना ही नहीं तो अश्लील पोस्टर एवं चित्रों के माध्यम से भोगवादी मानसिकता का प्रदर्शन होता है। उन्होंने कहा कि महिलायें न तो शक्ति से कम हैं और न बुद्धि में, वास्तविक मायने में हमारा आत्मविश्वास ही इसके लिए जिम्मेदार है। इसलिये विद्यार्थी परिषद् की छात्राओं एवं महिलाओं को समाज में जागृति उत्पन्न कर नारी शक्तिकरण की आवाज को बुलन्द करने के लिये अग्रेसर बनकर आगे आना चाहिए। सुश्री गीता ताई ने अहिल्या बाई का स्मरण दिलाते हुए

कहा कि उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से प्रेरणा लेकर महिलाओं को नई शक्ति एवं संगठन के द्वारा आत्मविश्वास के साथ आगे आना चाहिए। तभी हम विजयी होकर भारत को विश्व में आदर एवं प्रतिष्ठा दिलाने के वास्तविक हकदार होंगे।

इस अवसर पर ब्रज प्रदेश की सम्भाग प्रमुख श्रीमती ललितेश जैन ने विद्यार्थी परिषद् की रीति-नीति तथा संगठन कार्य की जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थी वर्ग को अपने रचनात्मक, संगठनात्मक एवं आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र शक्ति के समक्ष नेतृत्व की सार्यक दिशा निर्धारित करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी में संगठन कौशल्य, चरित्र संपन्नता, संघर्ष क्षमता का विकास किया जा सके।

सम्मेलन में मुख्य अतिथि समाज सेविका बीना कपूर, विशिष्ट अतिथि डॉ. शशि तिवारी, मुख्य वक्ता प्रांत छात्रा प्रमुख डॉ. रेनु माथुर कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती रेनु अग्रवाल, परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय गोयल उपस्थित थे। उद्घाटन डॉ. बीना मिश्रा ने सरस्वती मी एवं स्वामी विवेकानन्द के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित



ओमप्रकाश शर्मा

शिव ज्योतिष केन्द्र

यमुना बाजार हनुमान मंदिर, बेला रोड, दिल्ली

उनकी मिट्टी से भी खुशबू-ए-वतन आती है

26 जनवरी 1980। आंध्र प्रदेश में बारांगल स्थित काकतिया विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नक्सलवादी संगठन आर.एस.यू. का एक सदस्य छात्र सामने आता है और राष्ट्रीय ध्वज को उतार कर उसे जलाने का प्रयास करता है। क्षण भर बाद ही एक अन्य छात्र तेजी से उठता है और उस नक्सलवादी छात्र से राष्ट्रध्वज छीन लेता है तथा पूरी ताकत से वन्दे मातरम् एवं भारत माता की जय के नारे लगाता है।

सैकड़ों छात्रों, शिक्षकों एवं स्वयं कुलपति की उपस्थिति में हुई घटना का कोई गवाह नहीं मिलता। भारत माता की जय के नारे लगाने वाला वही छात्र सामा जगनमोहन रेड्डी फिर आगे आता है और घटना का मुख्य गवाह बनता है। 21 अप्रैल 1982 को न्यायालय से वापस आते समय नक्सलवादियों का एक दल नगर के व्यस्ततम स्थान हनमकोंडा मुख्यमार्ग पर उसे चाकूओं से गोद डालता है। कई घंटे तक उसका शव सड़क के बीचों-बीच पड़ा रहता है पर कोई पास अपने का सहस नहीं करता।

जगनमोहन रेड्डी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से एक था। अर्थशास्त्र में एम.ए. करने के बाद वह लों का विद्यार्थी था साथ ही सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। राष्ट्रवाद के जिस मंत्र का उसने वरण किया था, राष्ट्रध्वज की रक्षा के लिये अपना जीवन देकर उसे सार्थक किया। उसकी हत्या अभावप व संघ विचार के संगठनों को भयभीत करने का प्रयास था परंतु उसने कार्यकर्ताओं की संकल्प शक्ति को बढ़ाया ही।

हैदराबाद का अभावप कार्यकर्ता एवं राजकीय पॉलिटेक्निक, हैदराबाद का छात्रसंघ उपाध्यक्ष आर. जयनंद नक्सलवादियों की हिटलिस्ट में पहले से था। इस आशय के पर्चे भी पहले बीट दिये गये थे जिसके बाद विद्यार्थी परिषद ने पुलिस से संरक्षण की माँग की थी जो कि उपलब्ध नहीं कराई गई। 20 मई, 1988 को पीच अतिवादियों ने सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन पर गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। सैकड़ों यात्रियों और पुलिस की उपस्थिति में हत्यारे टहलते हुए चले गये।

नगुलामुरम गोव के कैसत्रा की हत्या जहाँ केवल इसलिये कर दी गई क्योंकि उसने नवंबर 1990 में राम जन्मभूमि, अयोध्या में कारसेवा में भाग लिया था वहीं डुडेड़ा गोव, जिला मेंडक के पेडयाद गिरि तथा नरसिम्हा रेड्डी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवर्तमान सरसंघचालक पूज्य रज्जू भैया के कार्यक्रम में अपने गोव के लोगों को ले जाने के अपराध में पीट-पीट कर मार डाला गया। करीम नगर के मानेगुडम् के निवासी गोरे मियी को पीपुल्स चार ग्रुप और जन शक्ति के नक्सलवादियों ने पोस्टर लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र देने को कहा था। त्यागपत्र न देने पर 13 अगस्त 1996 को कुल्हाड़ी से काट कर उनकी हत्या कर दी गई।

प. बंगाल के हुगली जिले के जगन्नाथपुर में रा.स्व.संघ के जिल्हा शरीरिक प्रमुख दयाल सिन्हा रॉय एवं उनके भाई हर्षवर्धन सिन्हा रॉय की हत्या कर दी। हत्या के लिये कुल्हाड़ी और फावड़ों का प्रयोग किया गया। एक दिन पहले भी माकपाई गुण्डों ने उनके घर पर हमला किया था पर वे नहीं मिले। हर्षवर्धन ने इस घटना की रिपोर्ट थाने में लिखाई और पुलिस सुरक्षा की माँग की। यह सुरक्षा उन्हें उपलब्ध भी कराई गई किन्तु अगले दिन प्रातः 7 बजे अचानक यह सुरक्षा हटा ली गई और आधे घंटे के अंदर ही उनके घर पर हमला हो गया।

एवूर के स्वयंसेवक पुष्परंजन पर माकसवादी गुण्डों द्वारा 22 अक्टूबर 1983 को हमला किया गया। एक अन्य कार्यकर्ता वासवन अपने कुछ सहयोगियों के साथ पुष्परंजन की सहायता के लिये घटनास्थल पर पहुंचा जहाँ उन पर भी हमला हुआ। वासवन उनकी गिरफ्त में आ गया जिसे माकसवादी गुण्डों द्वारा भयंकर यातनायें दी गईं। उसके बाल जला दिये गये तथा गुप्तांग काट दिया गया। अंततः उसे एक नहर में डुबोकर मार डाला गया। दो दिन बाद उसका शव खोजा जा सका।

धर्मराजन पूर्व सैनिक था एवं माकपा का समर्थक था। दो वर्ष पूर्व ही उसकी व उसके परिवार की निकटता रा.स्व.संघ से बढ़ी। माकसवादियों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। 12 जून, 1982 को चेंगनूर में उनके घर के बाहर दिन-दहाड़े धर्मराजन और उनकी पत्नी यशोदा की हत्या कर दी गई। उनकी पुत्री गिरिजा, जो सेविका समिति की कार्यकर्ता थी, को साइकल की चेनो से बर्बरतापूर्वक पीटा गया। संघ कार्यकर्ता हरिहर अय्यर की 6 दिसम्बर, 1987 को दिन-दहाड़े डी.वाई.एफ.आई. के गुंडों ने हत्या की। उनकी शवयात्रा पर भी हमला किया गया जिसमें विजयन नाम का कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुआ।

पालक्काड़ में मद्रास स्पिनिंग मिल के कर्मचारी रंगनाथन ने सीटू छोड़कर भारतीय मजदूर संघ की सदस्यता ग्रहण की। क्रुद्ध माकसवादियों ने 12 दिसम्बर, 1987 को मिल परिसर में ही रंगनाथन की हत्या कर दी। बाद में उन्होंने आठ अन्य मजदूर संघ कार्यकर्ताओं की हत्या की तथा 33 घरों को नष्ट कर दिया। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कौशल्या के कोर्टाट्याम स्थित निवास में घुसकर माकपा के कार्यकर्ताओं ने उन पर 22 मई 1991 को हमला किया। उन्हें राजकीय अस्पताल ले जाया गया। माकपाई गुंडों ने पुनः अस्पताल पहुंचकर उनकी चाकूओं से गोद कर हत्या कर दी।

आतंक का साम्राज्य कायम करने के लिये नक्सलवादियों ने महिलाओं तथा बच्चों तक पर निर्दयतापूर्वक हमले किये। सैकड़ों लोगों के अंग कुल्हाड़ी से काट दिये गये। सैकड़ों लोगों को चाकू से गोदा गया। अक्कूपल्ली के भूचन्द्र राव की वामुदेव राव और तेजेश्वर राव के दल ने हत्या करने के बाद

महिलाओं के समूह के सामने उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिये। एक हमलावर ने अपने हाथ मृतक के खून से भिगोकर दीवारों पर छापे लगाये। इसी दल ने एक अन्य घटना में मृतक का खून एक बर्तन में एकत्र कर उससे दीवारों पर नारे लिखे। एक अन्य दल ने अम्बतिकाम्बरम् गांव में हत्या के बाद मृतक के सिर को उसके घर के बाहर एक बांस के ऊपर लटका दिया।

हिंसा और अराष्ट्रीय गतिविधियों का यह कारोबार जिसे वामपंथी शब्दावली द्वारा चमकदार बनाकर भारत के आम मजदूर किसान के बीच क्रांति के रूप में आजादी के बाद से ही परोसा जा रहा है, उस तथाकथित विचारधारा की तर्कहीनता का प्रमाण है। किसी भी लोकतंत्र में सभी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने की संवैधानिक स्वतंत्रता होती है। भारत में भी यह सहज उपलब्ध है। यह भी सत्य है कि इस स्वतंत्रता का उपयोग भी उक्त तत्वों ने अपने बर्बरतापूर्वक मध्ययुगीन कृत्यों को छुपाने में किया है।

आतंकवाद, चाहे वह किसी भी रूप में हो, सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। तेलंगाना या बिहार के किसी सुदूर गांव में अपनी अदालत लगाकर उसमें किसी को भी छः इंच छोटा करने की सजा सुनाना उतना ही अमानुषिक तथा निंदनीय है जितना अफगानिस्तान में तालिबानी बर्बरता। आतंकवाद को खांचों में नहीं बांटा जा सकता। अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद जैसा विभाजन भी संभव नहीं है। हत्या सोदेश्य हो या निरुद्देश्य, चाहे उसके पीछे कितना भी मजबूत तर्क क्यों न हो, पाशविकता है, अपराध है।

यह लड़ाई, जो गत पांच दशकों से देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न नामों से जारी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ी जा रही है, वस्तुतः देश की अस्मिता एवं प्रभुसत्ता के संरक्षण की लड़ाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विचार परिवार ने इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के पीछे छिपे भयंकर खतरों को सबसे पहले अनुभव किया और यथासंभव चुनौती देने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप सर्वाधिक बलिदान भी उसे ही देने पड़े और सबसे ज्यादा आलोचना भी सहनी पड़ी।

जिन नागरिकों तथा समाज के जिन हिस्सों ने तटस्थता के लबादे में ढक कर अपनी भीरुता को छिपाये रखा उनको भले ही व्यक्तिगत हानि न उठानी पड़ी हो पर अराजकता के वातावरण में जीने के लिये वे भी अभिशप्त रहे हैं। जब दो-तीन या दस-पांच आतंकवादी या नक्सलवादी किसी राष्ट्रवादी कार्यकर्ता को दिन-दहाड़े कत्ल करते रहे तब पूरा गांव या वहां से गुजरते लोग मूकदर्शक बने रहे। इसी का व्याप भी वह घटना जब पचास हजार समर्थकों की उपस्थिति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या की गई और गवाह मिलना मुश्किल हो गया।

देश और दुनिया का नेतृत्व आज जिसे इतिहास की सबसे

भयंकर घटना कहकर निरूपित कर रहा है। वास्तव में उसके बीज उन छोटी घटनाओं में छिपे थे जिनकी ओर दशकों पहले राष्ट्रवादी विचार के लोगों ने इंगित किया था। व्यक्तिगत अथवा राजनैतिक कारणों से अराजक तत्वों का समर्थन करने वालों ने, उन्हें पैसा और हथियार मुहैया करवाने वालों ने, चाहे वे राजनैतिक दल हों या अमेरिका सरीखे देश, यह नहीं सोचा कि जिस आग को वे हवा दे रहे हैं वह एक न एक दिन उन तक भी पहुंचेगी।

जो लोग वातानुकूलित कक्षों में बैठकर हत्यारों के मानवाधिकार की वकालत करते थे वही लोग आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद दूरदर्शन पर आतंकवाद को समाप्त करने की बातें कर रहे हैं। केवल इसीलिए, क्योंकि उनका धर्मपिता अमेरिका भी यही भाषा बोलने लगा है।

इसके विपरीत देश में एक ऐसा वर्ग मौजूद है जो स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों का लाभ उठाते हुए आज भी शत्रु की भाषा बोल रहा है। उसमें इतना दुस्साहस है कि संसद पर हमले के आरोपी जिलानी के समर्थन में न सिर्फ आगे आता है बल्कि उसकी सहायता के लिये सार्वजनिक चन्दा भी करता है विचारधारा अथवा व्यक्ति स्वातंत्र्य की आड़ में देश की संप्रभुता को चुनौती बन चुके इन गिरोहों पर कठोर प्रहार किया जाना आज की आवश्यकता है।

ऐसे समय में जब विश्व समुदाय आतंकवाद के विरुद्ध युद्धरत है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के प्रमुख कार्यकर्ता प्रो. एस.बी. शेषगिरिराव ने स्व. श्यामाप्रसाद मुखर्जी एवम् पं. दीनदयाल उपाध्याय सहित सैकड़ों स्वयंसेवकों एवं समान विचार के संगठनों के कार्यकर्ताओं का जीवन लेने वाली बर्बर घटनाओं को Struggle against National Spitter : "Martyrdom of Swayamsevaks" नामक पुस्तक में संकलित किया है।

यह पुस्तक आतंकवाद के एक प्रमुख पक्ष इस्लामिक आतंकवाद, जिस पर आज सारी दुनिया में बहस छिड़ी है, के साथ-साथ आतंकवाद के अन्य स्वरूपों पर भी प्रकाश डालती है तथा इसकी विभीषका को समझने के लिये एक बड़ा कैनवस उपलब्ध कराती है। साथ ही इस विचार को बल प्रदान करती है कि आतंकवाद के विरुद्ध यह एक समग्र लड़ाई है जिसके उन्मूलन के लिये समग्रचिंतन की आवश्यकता है। टुकड़ों में बांटकर न इस समस्या को समझना संभव है न ही इसका समाधान।

पुस्तक का प्रकाशन हैदराबाद स्थित Martyrs' Memorial Research Institute (MMRI) ने किया है। 26 पृष्ठीय सचित्र पुस्तक का मूल्य 150/- मात्र है। तथा इसे ZMMRI, 8, सत्य नगर, फ्लैट्स, विद्यानगर, हैदराबाद-500044 अथवा साहित्य निकेतन, 3-4-852 केशव निलयम, बरकतपुरा, हैदराबाद-500018 से प्राप्त किया जा सकता है।

502 का वादा...

दाम वाजिब, स्वाद ज्यादा !

502

पताका चाय



502 पीने वालों का
अन्दाज़ है कुछ और



व्यापारिक पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : निर्माता: 502 पताका ग्रुप
A-3/17 भजनपुरा, दिल्ली-53 फोन: 2175002/3/4 फैक्स: 011-2262282

EXCEL BOND

If the power of words is a potent corporate weapon,
this paper is your aid to corporate power

Paper has changed the course of history



Now this paper can change the course of your business

Presenting Excel Bond

With a never before whiteness and crispness. Versatile enough even for die cutting, embossing and raised printing. Making it ideal for exclusive letterheads, envelopes, complimentary slips and even brochures, annual reports, direct mail and booklets. All with an amazing economy! But don't take our word for it. Just pick it up and examine it yourself. Limited Edition Excel Bond Sample Book available at your nearest retailer. Or write to us for your complimentary copy.



JK CORP
LIMITED

Marketing Dept. (P&B), 3rd Floor, Nehru House, 4, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110 002. Tel.: 3311112/3/4/5 Fax: 011-3712680.